लखनऊ

गुरुवार, 30 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 331

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

हीरे की परख करनी हो तो अंधेरे का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

पेपर लीक बिल पर लोकसभा में राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा आरोप, सदन में जमकर हंगामा, भाजपा बोली- सबूत दिखाओ... वरना मांगो माफी

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में बुधवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यानी की पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। जहां सबसे ज्यादा हंगामा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर देखने को मिला जहां उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और छात्रों के हालिया प्रदर्शनों का मुद्दा भी उठाया।

राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे थे और सरकार से नाराज थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और पैलेट गन चलाने की अनुमति गृह मंत्री की ओर से दी गई थी। इस बयान के बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

स्पीकर ने दी चेतावनी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर सीधे आरोप लगाने के बजाय जांच की मांग की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री को लेकर कही गई कुछ टिप्पणियां सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगी। इससे पहले राहुल गांधी के भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों पर भी विवाद हुआ था, जिन्हें बाद में लोकसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्णय लिया गया।

अखिलेश यादव ने उठाया सवाल

हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों पर हुई कथित फायरिंग का आदेश किसने दिया था। इस पर किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगाया है और बिना प्रमाण ऐसे बयान देना उचित नहीं है।

लोकसभा में राहुल गांधी के 'अंधभक्त' वाले बयान पर हंगामा, शिक्षा व्यवस्था और आरएसएस पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में उस समय माहौल गर्मा गया, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक छात्रा के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए 'अंधभक्त' शब्द का इस्तेमाल किया। इस टिप्पणी के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि एक छात्रा ने लोगों को तीन श्रेणियों—विद्यार्थी, मूर्ख और अंधभक्त—में बांटकर समझाया। उन्होंने छात्रा के हवाले से कहा कि 'अंधभक्त वह व्यक्ति होता है, जो यह मान लेता है कि कोई दूसरा व्यक्ति ही भगवान है।' इस टिप्पणी के बाद लोकसभा में कुछ समय के लिए हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के छात्रों का गुस्सा केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगी शिक्षा, निजीकरण और बार-बार होने वाले पेपर लीक जैसी समस्याओं ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं दोबारा परीक्षा होती है तो कहीं नहीं, जिससे छात्रों के बीच असमानता की भावना पैदा होती है।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की

आर्यावर्त क्रांति

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार सुबह नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ, दादागुरु महंत दिग्विजयनाथ, योगीराज बाबा गंभीरनाथ और नाथ परंपरा के सभी गुरुओं की भी विधिवत पूजा-अर्चना की। बयान के अनुसार, गोरक्षपीठाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए जनकल्याण के लिए उनके मार्गदर्शन के प्रति आभार जताया।

गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा की विशेष पूजा-अर्चना बुधवार तड़के शुरू हुई और सामूहिक आरती के साथ संपन्न हुई। आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सबसे पहले नाथ परंपरा के आदिगुरु भगवान गोरखनाथ के दरबार में नमन किया और फिर विशेष पूजा-अर्चना की।

इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित सभी देवी-देवताओं के मंदिरों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ और अन्य दिवंगत गुरुओं की समाधियों पर भी पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। बयान के मुताबिक, पूजा-अर्चना संपन्न होने के बाद गुरु पूर्णिमा की पारंपरिक सामूहिक आरती की गई।

'नए उद्योगों के दावे, पुराने उद्योग बंद': शिवसेना यूबीटी ने सामना में सरकार से पूछा सवाल; कहा- जिम्मेदार कौन?

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) ने केंद्र पर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने बुधवार को अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लोकसभा में पेश केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में देशभर में 1,21,805 एमएसएमई इकाइयां बंद हो गईं। इसके कारण लाखों युवाओं की नौकरियां चली गईं। शिवसेना (यूबीटी) ने संपादकीय लिखा, 'पिछले 12 वर्षों से देश में पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं। नए उद्योग शुरू करने की बातें हो रही हैं। जिस शासन में युवाओं के हाथों में रोजगार देने के बजाय उनके मन में धार्मिक उन्माद भरा जाए, वहां इससे अलग परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है?'

कर्मचारी की बर्खास्तगी की वैधता से पहले विभागीय जांच की पवित्रता का परीक्षण जरूरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की बर्खास्तगी की वैधता से पहले विभागीय जांच की पवित्रता का परीक्षण जरूरी है। जांच में खोट मिलने पर नियोक्ता को बचाव का अवसर दिए बिना कर्मचारी को दोषमुक्त घोषित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने मेसर्स शाही एक्सपोर्ट हाउस की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। साथ ही कर्मचारी के पक्ष में सुनाए गए नोएडा श्रम न्यायालय के निर्णय को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। मामले को श्रम न्यायालय के पास भेजते हुए तीन महीने में नियोक्ता व कर्मचारी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया है। मामले में नियोक्ता ने कर्मचारी के खिलाफ लगे विभिन्न आरोपों पर विभागीय जांच कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर अक्तूबर 2001 में कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके खिलाफ कर्मचारी ने नोएडा श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान श्रम न्यायालय ने सेवा समाप्ति के अलावा यह वाद बिंदु भी तय किया कि क्या विभागीय जांच निष्पक्ष थी। हालांकि, इस मुद्दे का पहले निर्णय करने के बजाय श्रम न्यायालय ने आरोपों के गुण-दोष पर भी साथ-साथ साक्ष्य दर्ज कर लिए और अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि विभागीय जांच निष्पक्ष नहीं थी।

योग गुरु रामदेव का 'आज़ादी' नारों पर बड़ा बयान, बोले- देश संविधान से चलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। योग गुरु रामदेव ने बुधवार को कहा कि ब्राह्मणवाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के ख़िलाफ़ 'आज़ादी' के नारों से चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान सभी समुदायों को समान अधिकार देता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि भले ही ब्राह्मणवाद या RSS के ख़िलाफ़ नारे लगाना गलत है, लेकिन संविधान सभी समूहों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। रामदेव ने कहा कि देश सड़कों से नहीं चलेगा। देश सिर्फ़ संसद से चलेगा। शिक्षा मंत्री कौन होगा, यह सड़कों पर तय नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री और संसद ही यह तय करेंगे। ब्राह्मणवाद और RSS को निशाना बनाने वाले 'आज़ादी' के नारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रह्लाद जोशी ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए और RSS से राष्ट्रवाद सीखा, तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रामदेव ने आगे कहा कि देश का संविधान दलितों और शोषितों के साथ-साथ ब्राह्मणों को भी अधिकार देता है। इसलिए, ब्राह्मणवाद को बुरा-भला कहना असंवैधानिक है। शूद्रों को बुरा-भला कहना भी असंवैधानिक है।

उन्होंने जंतर-मंतर पर 'जेनरेशन Z' के विरोध प्रदर्शनों की भी आलोचना की और कहा कि इन प्रदर्शनों से भारत की बदनामी हुई। रामदेव ने कहा कि जेनरेशन Z जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुई और भारत को बदनाम किया। गाली-गलौज हमारी संस्कृति या स्वभाव नहीं है। हमने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया है।

मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर चार अगस्त से वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मुजफ्फरनगर/गाजियाबाद। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिये खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग चरणों में यातायात पर सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी और कांवड़ियों की सुगम आवाजाही के लिए चार अगस्त से मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन पाबंदियों से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के बीच यात्रा पर असर पड़ने की सम्भावना है और रास्ते बदले जाने की वजह से यात्रियों को लंबा सफर करना पड़ सकता है और बस तथा टैक्सी का किराया भी अधिक देना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि 30 जुलाई से मुख्य रास्तों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी जबकि चार अगस्त से जिले में दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंग नहर मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

कुमार ने संवाददाताओं से कहा, यात्रा के दौरान कांवड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से हो, इसके लिए वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा। एसएसपी ने बताया कि मार्ग परिवर्तन योजना के तहत हरिद्वार और सहारनपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को देवबंद, पचेंडा, मीरापुर और मेरठ के मवाना से होते हुए दिल्ली तक भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि वापसी का यातायात भी इसी रास्ते से होगा।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मार्ग परिवर्तन के तहत निर्धारित रास्तों पर बसें चलाने का प्रबंध किया है, हालांकि अतिरिक्त दूरी की वजह से यात्रियों को अधिक समय लग सकता है और किराया भी ज्यादा देना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा के तहत भगवान शिव के भक्त हरिद्वार तथा गंगा के अन्य तटों से पवित्र गंगा जल लाते हैं और उसे पैदल चलकर अपने गृहनगरों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। यह यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को सम्पन्न होगी।

'हम बहुत जल्द दोबारा सड़कों पर उतरेंगे'

अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, अब क्यों सरकार को चेतावनी दे रही सीजेपी?

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के अपने वादे से पीछे हट रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का सहारा ले रही है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर छात्रों का उत्पीड़न नहीं रुका और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो पार्टी जल्द ही फिर से सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा, '20 जुलाई को छात्रों ने पुलिस की लाठियां और खून-खराबा झेला। अगर सरकार इतने पर भी नहीं चेती और युवाओं का उत्पीड़न जारी रहा, तो हम बहुत जल्द दोबारा सड़कों पर उतरेंगे।'

यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया, जबकि पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी।

'सरकार अदालत का हवाला देकर वादा निभाने से बच रही'

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि सरकार ने पहले सार्वजनिक रूप से भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और पुराने मामले भी वापस लिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कह रही है कि मामला अदालत में विचाराधीन है। दास ने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि मंगलवार तक सरकार लिखित आश्वासन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाना बनाकर अपने वादे से पीछे हट रही है।'

'एफआईआर वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका'

सौरव दास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि सरकार एफआईआर वापस नहीं ले सकती। उनके मुताबिक, एफआईआर वापस लेने का अधिकार सरकार के पास है और आदेश की गलत व्याख्या कर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के खिलाफ अदालत के आदेश का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और उसे प्रदर्शनकारियों से किए गए वादे पूरे करने चाहिए।

संक्षेप

कोयला आवंटन केस में मनमोहन सिंह पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ गया? ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को औपचारिक रूप से बरी कर दिया। कोर्ट ने 2015 के उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें आरोपी के तौर पर तलब किया गया था—जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दो बार क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा कि उन पर मुकदमा चलाने का कोई ठोस कारण नहीं था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच का यह आदेश सिंह को मरणोपरांत कानूनी रूप से सही ठहराता है। सिंह का निधन दिसंबर 2024 में हुआ था, जबकि समन जारी करने के आदेश के खिलाफ उनकी अपील एक दशक से भी ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। बुधवार का आदेश न केवल दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खत्म करता है, बल्कि CBI के इस निष्कर्ष को भी स्पष्ट रूप से सही ठहराता है कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसके साथ ही, UPA के दौर में कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद से जुड़े सबसे अहम आपराधिक मामलों में से एक का अंत हो गया है। बेंच ने यह माना कि सिंह के निधन के कारण अपील तकनीकी रूप से बेअसर हो गई थी, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले की कानूनी वैधता की जांच करना ज़रूरी था, क्योंकि जांच एजेंसी के दो बार यह निष्कर्ष निकालने के बावजूद कि उनके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, पूर्व प्रधानमंत्री को समन जारी किया गया था।

भाजपा सांसद ने केंद्र सरकार के सामने उठाया मणिपुर पुनर्वास का मुद्दा, कहा- पीड़ितों की वापसी जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर की सांसद ए शारदा देवी ने बुधवार को केंद्र से राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अलग-अलग प्रस्तावों को जल्द से मंजूरी देने का आग्रह किया, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के कल्याण और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने संसद भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इसके साथ ही मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के बीच राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राज्यसभा सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मणिपुर सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और मांगों को मंजूरी देने में सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। मौजूदा संकट से प्रभावित समुदायों के लिए समय पर हस्तक्षेप और बेहतर समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चर्चाओं में विशेष रूप से आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मणिपुर के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा और बैठक के दौरान उठाए गए अनुरोधों पर उचित विचार करेगा।

जयराम रमेश ने एनईपी को 'नागपुर शिक्षा नीति' कहा, बिना संसदीय चर्चा लागू करने का आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। सीनियर कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने 31 जनवरी, 2026 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की छठी सालगिरह पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कहा और आरोप लगाया कि इसे बिना संसदीय चर्चा के लागू किया गया था। X पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि आज मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को NEP (नई शिक्षा नीति) को अपनाए जाने की छठी सालगिरह है। NEP 2020 पर संसद में कभी चर्चा नहीं हुई और न ही इसे शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से मंज़ूरी मिली। उन्होंने सरकार पर NEP के तहत अहम रेगुलेटरी बॉडीज़ और पहलों को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज NEP की नींव हिल गई है। NTA की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो पूर्व मंत्री इसके सबसे बड़े प्रचारक थे और जिन्होंने राज्य सरकारों पर NEP लागू करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डाला था, उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' का मामला संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया है, जो ठंडे बस्ते में पड़ी है; NDA सहयोगियों के विरोध के कारण पिछले तीन हफ़्तों में कम से कम दो बार इसकी बैठकें रद्द करनी पड़ी हैं। रमेश ने मौजूदा पॉलिसी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शुरू की गई 'नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन' से की और संसदीय सहमति तथा पॉलिसी के लंबे समय तक रहने वाले असर के महत्व पर ज़ोर दिया।

परिवार के वैभव का कत्ल

साइकिल लेकर निकला था मासूम, टीचर ने इसलिए अपहरण कर कारोबारी के बेटे को मार डाला

सीसीटीवी फुटेज की जांच में पड़ोस में रहने वाले सर्वेश भट्ट की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर उसके घर के बेसमेंट से बच्चे का शव बरामद किया गया।

- डॉ. कौस्तुभ, एसएसपी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। गोरखपुर के खजनी कस्बे के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण वर्मा के बेटे हनुमान सदमे में हैं। पहले पत्नी की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था अब बेटे वैभव के कत्ल से खुशियां तबाह हो गई हैं। वहीं दादा और दादी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वे सबसे दुलारे पौत्र वैभव के जाने का गम भुला नहीं पा रहे हैं। जिस आंगन में कुछ दिन पहले बहू की चिता की राख ठंडी हुई थी, वहीं अब मासूम की अर्थी उठने से तीन पीढ़ियों का दर्द एक साथ छलक पड़ा।

परिवार के मुखिया लक्ष्मी नारायण वर्मा और उनकी पत्नी द्रौपदी देवी के लिए यह सदमा असहनीय है। लक्ष्मी नारायण के पांच बेटे और तीन बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे त्रिभुवन वर्मा भी खजनी में कारोबार करते हैं। दूसरे नंबर के बेटे हनुमान वर्मा और सबसे छोटे बेटे उमाशंकर खजनी में सराफा कारोबार संभालते है। जबकि तीसरे नंबर के बेटे द्वारिका वर्मा एम्स में डॉक्टर हैं। उनसे छोटे गौरीशंकर वर्मा की घंटाघर में दुकान है। बड़ा संयुक्त परिवार होने के कारण घर में हमेशा चहल-पहल रहती थी लेकिन अब उसी घर में चीख पुकार मची हुई है। करीब एक महीने पहले हनुमान की पत्नी श्वेता के निधन के बाद पूरा परिवार उनके तीनों बच्चों को संभालने में जुटा था। सबसे छोटा होने के कारण वैभव दादा-दादी की आंखों का तारा था। द्रौपदी उसे पलभर भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थीं। दादा लक्ष्मी नारायण अक्सर उसे दुकान तक साथ ले जाते थे। पिता हनुमान भी बेटे की मासूम मुस्कान में पत्नी के बिछड़ने का दर्द भुलाने का प्रयास कर रहे थे।

वैभव की खिलखिलाहट संयुक्त परिवार की थी पहचान

वैभव की खिलखिलाहट संयुक्त परिवार की पहचान थी। स्कूल से लौटकर वह कभी साइकिल चलाता, कभी अपने भाइयों और दोस्तों के साथ खेलता था। कभी दादा-दादी के कमरे में जाकर उनसे बातें करता तो उसकी शरारतों पर पूरा परिवार मुस्कुराता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि रोज की तरह खेलने के लिए निकला यह बच्चा फिर कभी घर नहीं लौटेगा।

रातभर हर दस्तक और हर फोन कॉल पर बंधती रही उम्मीदें

सोमवार शाम जैसे-जैसे बीतती गई, परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। रातभर हर दस्तक और हर फोन कॉल पर उम्मीद बंधती रही कि शायद वैभव मिल जाएगा लेकिन मंगलवार को उसके नहीं रहने की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। दादा-दादी की चीखें सुनकर आसपास के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। पिता हनुमान के सामने एक महीने के भीतर पत्नी और बेटे दोनों को खोने का असहनीय दर्द था।

एक माह के भीतर उजड़ीं दो बार खुशियां

खजनी कस्बे के लोगों का कहना है कि वर्मा परिवार वर्षों से व्यापार और सामाजिक सरोकारों के लिए जाना जाता है। ऐसे परिवार पर लगातार दो बड़े वज्रपात ने पूरे कस्बे को गमगीन कर दिया। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ सिर्फ एक मासूम को विदाई देने नहीं आई थी, बल्कि उस परिवार के दुख में सहभागी बनने पहुंची थी, जिसकी खुशियां एक महीने के भीतर दो बार उजड़ गईं। अब घर में वैभव की किताबें, साइकिल और खिलौने तो हैं लेकिन उन्हें संभालने वाली मासूम हमेशा के लिए खामोश हो चुका है।

मासूम की अपहरण के बाद हत्या

गोरखपुर के खजनी कस्बे के सराफा कारोबारी हनुमान वर्मा के 10 वर्षीय बेटे वैभव वर्मा के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद साइकिल लेकर घर से निकला बालक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। करीब 24 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी कंप्यूटर शिक्षक सर्वेश भट्ट को गिरफ्तार कर उसके घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया। घटना के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग जाम कर खजनी थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार, खजनी कस्बे के सराफा कारोबारी का सबसे छोटा बेटा वैभव सोमवार दोपहर करीब दो बजे स्कूल से घर लौटा था। उसने स्कूल बैग रखा, यूनिफॉर्म बदली और नई साइकिल लेकर घर से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी साइकिल लावारिस हालत में मिली, जबकि पास के खेत में उसकी एक चप्पल बरामद हुई। इसके बाद परिजन ने पुलिस को सूचना दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर वैभव के पीछे पड़ोस में रहने वाला कंप्यूटर शिक्षक सर्वेश भट्ट जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने मंगलवार दोपहर सर्वेश के घर की तलाशी ली। इस दौरान उसके मकान के बेसमेंट से बालक का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हत्या के कारण और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

बच्चे का शव मिलने की सूचना फैलते ही खजनी कस्बे में भीड़ जुट गई। आक्रोशित व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने खजनी-सिकरीगंज और खजनी-मल्हनपार मार्ग जाम कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग खजनी थाने पहुंच गए और घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के एनकाउंटर, उसके मकान पर बुलडोजर चलाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोर सजा दिलाने की मांग की।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉ. कौस्तुभ, डीएम दीपक मीणा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। भीड़ के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। एहतियातन आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। देर तक चली बातचीत और अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। वैभव का शव बरामद होने के बाद खजनी कस्बे में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन और स्थानीय लोगों ने मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे खजनी-सिकरीगंज-बांसगांव मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सूचना मिलते ही डीएम, एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। इस दौरान खजनी थाने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गईं, जहां पुलिस से कहासुनी और हल्की झड़प की स्थिति बनी। अधिकारियों के आश्वासन और लगातार चली वार्ता के बाद शाम करीब 4:20 बजे जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल कराया गया। एहतियात के तौर पर पूरे कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया है।

गुरु पूर्णिमा पर पूजन करते शिव शंकर तीर्थ डंडी स्वामी

कुड़वार सुल्तानपुर। अपनी मेहनत व लगन से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में सामाजिक विषय से प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है।परिणाम आते ही गांव वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय क्षेत्र के पूरे दयाराम तिवारी कुड़वार गांव निवासी अभिषेक तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए टीजीटी में सामाजिक विषय से प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।अभिषेक ने प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी विद्यालय कुड़वार,माध्यमिक बीपी इंटर कॉलेज कुड़वार व उच्च माध्यमिक पीपी इंटर कॉलेज वलीपुर,स्नातक गणपत सहाय स्नाकोत्तर महाविद्यालय सुल्तानपुर से प्राप्त की है। बीएड केएनआई से उत्तीर्ण किया था।अभिषेक के पिता प्रदीप तिवारी बढ़नपुर जूनियर विद्यालय में प्रधानाध्यपक है।पिता की प्रेरणा व दिशा निर्देशन में अभिषेक ने प्रदेश में स्थान प्राप्त कर परिवार का नाम रोशन किया है।

सांप काटने से अधेड़ महिला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

आर्यावर्त संवाददाता

लंभुआ सुल्तानपुर। कोतवाली क्षेत्र के भगौतीपुर गांव में सांप काटने से एक महिला की हालत नाजुक हो गई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ, जब महिला लोहे की बखारी से गेहूं निकालने गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

भगौतीपुर निवासी राजाराम की पत्नी भगनी (53) गृहणी हैं। मंगलवार की देर शाम वे घर के कमरे में रखे लोहे की बखारी से गेहूं निकालने गई थी। बताते हैं कि बखारी के नीचे ही मौजूद एक विषधर सांप ने उन्हें काट लिया। सांप के काटने से उनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन परिजन उन्हें लेकर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। पर, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वे अपने पीछे पांच बेटे - बेटियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।तहसील प्रशासन द्वारा मौके पर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट भेज दी गई है।जल्द ही परिवार को शासन से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो जाएगी।

पुलिस मुठभेड़ में दो गो तस्कर गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। मंगलवार की रात गो कशी की घटना को अंजाम देने जा रहे गो कशो से अखंड नगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई।मुठभेड़ में एक गोकश गोली लगने से घायल हो गया। जबकि दूसरा गिरफ्तार हो गया।उसके अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए।

अखंड नगर पुलिस के अनुसार मंगलवार बुधवार की रात चेकिंग के दौरान कुंदा भैरवपुर सर्वेश लेन अंडर पास के पास पुलिस ने बाइक सवार लोगों को रुकने का इशारा किया तो उन लोगों द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई।पुलिस की जवाबी फायरिंग में अब्दुल सलाम पुत्र खलील निवासी हाजीगंज थाना चांदा गोली लगने से घायल हो गया जबकि उसका भाई रियाज को पुलिस ने वैसे ही गिरफ्तार कर लिया।घायलावस्था में सलाम को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल भेजा।जहां उसका इलाज हुआ।गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 12 बोर तमंचा,कारतूस,एक लोहे का चापड़, थीहा,बाइक आदि बरामद किया।आरोपी अब्दुल सलाम को खिलाफ एक मुकदमा चांदा थाने में दर्ज था।जबकि रियाज के खिलाफ कुल 10 मुकदमे दर्ज है।गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक अखंडबनगर धीरेन्द्र वर्मा,उपनिरीक्षक संतोष कुमार,उपनिरीक्षक कन्हैया कुमार पांडेय सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।एसपी चारु निगम ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25 हजार रुपए का इनाम देकर हौसला अफजाई की।

दांतों से कार खींच रहा नरेंद्र, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहा, अनूठी कांवड़ यात्रा

आर्यावर्त संवाददाता

हापुड़. अलीगढ़ के छज्जूपुर गांव के नरेंद्र अपनी अनोखी कांवड़ यात्रा के कारण इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। वे हरिद्वार से 11 लीटर गंगाजल और भगवान शिव की प्रतिमा को अपनी कार पर रखकर, अपने दांतों से कार खींचते हुए अपने गांव लौट रहे हैं। उनकी इस असाधारण शिवभक्ति को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, जो उनका जगह-जगह स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ सेल्फी व रील बना रहे हैं।

नरेंद्र ने 10 जुलाई को हर की पौड़ी, हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपनी कांवड़ यात्रा प्रारंभ की थी। इस यात्रा में उनके साथ उनके गांव के पांच अन्य शिवभक्त और एक 10 वर्षीय बालक भी शामिल है। कार के आगे लगा पंखा गर्मी में राहत प्रदान कर रहा है। नरेंद्र के अनुसार, यह यात्रा भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था, दृढ़ संकल्प और गहरी श्रद्धा का प्रतीक है।

यह यात्रा, जो हरिद्वार से शुरू हुई है, लगभग एक महीने तक चलेगी। नरेंद्र का लक्ष्य सावन माह के अंतिम सोमवार तक अपने गांव छज्जूपुर पहुंचकर प्राचीन महादेव मंदिर में गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। उनकी यह अनूठी कांवड़ यात्रा न केवल लोगों को आकर्षित कर रही है, बल्कि भक्ति और समर्पण की एक मिसाल भी पेश कर रही है।

रास्ते में श्रद्धालु नरेंद्र पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इस यात्रा की विशिष्टता के कारण, यह सामाजिक माध्यमों पर भी काफी लोकप्रिय हो रही है, जहां लोग उनके साथ रील बना रहे हैं। यह घटनाक्रम भक्ति, समर्पण और अनोखी यात्राओं के प्रति लोगों की रुचि को दर्शाता है।

गुरु पूर्णिमा पर हंडिया बाबा आश्रम में उमड़े श्रद्धालु, हुआ भंडारे का आयोजन

कुड़वार सुल्तानपुर। स्थानीय पावर हाउस के समीप स्थित हंडिया बाबा आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

कार्यक्रम की शुरुआत आश्रम के संत शिव शंकर तीर्थ डंडी स्वामी ने अपने शिष्यों के साथ हंडिया बाबा तथा आश्रम के संस्थापक विष्णु देव जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन-अर्चन से की। इसके बाद लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ सहित विभिन्न जनपदों से पहुंचे शिष्यों ने डंडी स्वामी का विधि-विधान से पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में रामचरितमानस पाठ का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

4 जून की रात चोरी, 81 लाख रुपये और एसआईटी... चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफे में क्या कहा?

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। इस महीने की शुरुआत में ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्कीकार किया गया था। दोनों ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा था, अब इसकी डिटेल्स सामने आई है।

इस्तीफा पत्र में चोरी की घटना, ट्रस्ट की शुरुआती कार्रवाई, 81 लाख रुपये की वापसी, एसआईटी जांच की सिफारिश और दोनों के पद छोड़ने की पूरी वजह बताई गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा भी निरर्थक और अनर्गल बयान दिए गए, जिससे विवाद और बढ़ा। इस्तीफा पत्र के अनुसार, 4 जून की रात दानपात्र की गिनती के दौरान 5-6 युवकों द्वारा चोरी किए जाने की जानकारी एक ट्रस्टी को मिली। 5 जून की सुबह सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें कुछ युवकों की पहचान होने का दावा किया गया।

संबंधित युवकों से पूछताछ का निर्णय लिया गया। दावा किया गया कि 5 जून की रात से 8 जून के बीच आरोपित युवकों और उनके परिजनों ने कुल 81 लाख रुपये ट्रस्ट को वापस लौटा दिए। इस्तीफा पत्र के मुताबिक, संबंधित सभी लोगों ने चोरी स्वीकार करते हुए लिखित स्वीकृति पत्र भी दिए। पत्र में कहा गया कि मामले की चर्चा बढ़ने पर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से SIT से जांच कराने का अनुरोध किया, ताकि पूरे प्रकरण का सत्य सामने आ सके।

पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने अनुरोध स्वीकार करते हुए 15 जून से एसआईटी जांच शुरू कराई। इस्तीफे में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने लिखा कि नीर-क्षीर विवेक होने तक ट्रस्ट के सभी कार्यों से स्वयं को दूर रख रहे हैं, इस पत्र को हमारा त्यागपत्र मानकर स्वीकार किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी गठित

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक नई एसआईटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऐसा किया गया है। इस नई SIT टीम की कमान लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस को दी गई है। इसके अलावा इस टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉ। गौरव ग्रोवर को भी शामिल किया गया है। SIT का पुनर्गठन सुप्रीम कोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के बाद किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया था।

मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी चुनावी कमान, हाथरस से करेंगे अभियान की शुरुआत

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। चुनावी रणनीति के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी मंथन शुरू हो गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है।

जानकारी के मुताबिक आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा से पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी की रणनीति के तहत आकाश सादाबाद में विधानसभा प्रभारी के नाम की घोषणा करेंगे और इसके बाद कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की

बैठक को संबोधित करेंगे।

BSP की योजना प्रदेशभर में विधानसभा स्तर पर प्रभारियों की घोषणा के साथ चुनावी अभियान को गति देने की है। इसके तहत आकाश आनंद विभिन्न जिलों में लगातार जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकें करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।

पार्टी का गिरता ग्राफ बना चिंता का सबब

BSP नेतृत्व का मानना है कि साल 2007 की पूर्ण बहुमत सरकार के बाद पार्टी लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में 2027 के चुनाव को देखते हुए संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाश आनंद को चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बनाया गया है।

अविन शर्मा के नाम का हो सकता है ऐलान

सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त को सादाबाद विधानसभा से पार्टी उम्मीदवार (विधानसभा प्रभारी) के रूप में अविन शर्मा के नाम की घोषणा की जा सकती है। BSP पहले विधानसभा प्रभारियों की घोषणा करती है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी घोषित करती है।

25 अगस्त को जेवर में जनसभा

पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार, सादाबाद के बाद 25 अगस्त को जेवर में भी आकाश आनंद की बड़ी जनसभा प्रस्तावित है। BSP नेतृत्व को उम्मीद है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में शुरू होने वाला यह अभियान संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को मजबूती देगा।

सादाबाद विधानसभा सीट का समीकरण

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता मुख्य रूप से हार-जीत तय करते हैं। सादाबाद हिंदू-बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र है, जहां जाट सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं और चुनावी जीत करने में उनका रोल सबसे अहम होता है।

अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुए

सादाबाद विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने यह सीट पांच बार जीती। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने तीन , BJP और जनता दल ने 2-2 बार यह सीट जीती है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार, भारतीय क्रांति पार्टी (BKD), जनता पार्टी, लोक दल, समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने एक-एक बार जीत हासिल की है। पिछले तीन चुनावों में तीन अलग-अलग पार्टियों ने इस सीट पर जीत हासिल की है।

2012 से 2022 तक के नतीजों पर एक नजर

2012 में समाजवादी पार्टी ने सादाबाद विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। पार्टी ने यहां से देवेंद्र अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने BSP के सतेंद्र शर्मा को 5,187 वोटों से शिकस्त दी थी।

2017 में BSP ने इस पर कब्जा किया था। पार्टी के उम्मीदवार रामवीर उपाध्याय ने RLD के डॉ। अनिल चौधरी को 26,590 वोटों से हराया था। हालांकि वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2022 में RLD ने यहां से जीत हासिल की थी। पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार रामवीर उपाध्याय को 6,437 वोटों से हराया था।

घायल गौ कश से अस्पताल में जानकारी लेते सीओ विनय गौतम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। खेत में पलेवा करते समय ट्रैक्टर फंस जाने के बाद निकालने गए पोस्टमास्टर की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के इमली गांव से जुड़ा है।गांव निवासी किसान दिनकर चतुर्वेदी(55)बुधवार को सुबह खेत जोतने गए थे।खेत में पलेवा लगाते समय ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया।ट्रैक्टर निकालते समय ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पलट गया।जिसमे किसान दिनकर चतुर्वेदी ट्रैक्टर के नीचे दब गया।हल्ला गुहार पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब तक उन्हें निकाला तब तक उनकी मौत हो गई।मृतक की पत्नी पुष्पा चतुर्वेदी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया।मृतक इमलीगांव डाकखाने में पोस्टमास्टर थे।मृतक के पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है। मां जसोदा देवी का रो रो कर बुरा हाल है।मृतक की बड़ी बेटी स्वाति विवाहित है। जबकि तृप्ति(23),दीप्ति(21) व बेटा श्रेयांश(16)है।जो कक्षा 10 का छात्र है।सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि सूचना पर दोस्तपुर थाने की पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्यवाही करके पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है।

डायरिया नियंत्रण व रोकथाम के लिए विशेष अभियान का शुभारम्भ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय-उप्र के अधिकारियों ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को डायरिया से पूरी तरह सुरक्षित बनाने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में आगामी 25 अगस्त तक डायरिया रोको अभियान (स्टॉप डायरिया कैम्पेन) चलाया जा रहा है। इसी के तहत वर्ल्ड ओआरएस डे पर बुधवार को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अलीगंज से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय-उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) डॉ. ए.के. सिंह ने मिड मीडिया कैम्पेन का विधिवत शुभारम्भ किया। अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रहीं हैं।

इस मौके पर डॉ. ए. के. सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने डायरिया से बचाव, कारण, उपचार और रोकथाम सम्बन्धी संदेशों वाले पोस्टर-बैनर और ऑडियो/वीडियो से सुसज्जित प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय में डायरिया के प्रति जन जागरूकता लाएंगे। ओआरएस-जिंक कार्नर का शुभारम्भ किया। पौध रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सन्देश भी दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी यह सन्देश दिया गया कि दस्त के दौरान माताएं बच्चों को ओआरएस का घोल व जिंक देने के साथ स्तनपान जारी रखें। इसके साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भी सम्पर्क करें। डॉ. ए.के. सिंह ने कहा कि डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपचार पूरी तरह संभव है। बच्चे को दिन में दो-तीन बार पतली दस्त हो तो ओआरएस का घोल और जिंक जरूर दें, क्योंकि यही इसका सही उपचार है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय-उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक नियमित टीकाकरण डॉ. अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष डायरिया रोको अभियान की थीम "स्वच्छ जल, समुचित उपचार-डायरिया से बचें हर बार" तय की गयी है, जो कि सन्देश देती है कि दस्त की स्थिति में जरूरी सावधानी बरती जाए तो उससे बच्चे को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके अलावा डायरिया से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशुओं को रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है, जिससे डायरिया से होने वाली मृत्यु को काफी हद तक रोका जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह ने कहा कि बारिश और उमस में बच्चा डायरिया की चपेट में कई कारणों से आ सकता है, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें।

एनएचएम-यूपी के महाप्रबन्धक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. मिलिंद वर्धन ने कहा कि डायरिया के प्रति समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और ओआरएस व जिंक की महत्ता को भलीभांति समझाने के लिए ही पूरे प्रदेश में 25 जून से 25 अगस्त के मध्य बड़े पैमाने पर स्टॉप डायरिया कैम्पेन चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी. एन. यादव ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स माताओं और परिवार वालों को यह भली भांति बताएं कि ओआरएस का घोल और जिंक बच्चे को सिर्फ डायरिया से ही नहीं बचाता बल्कि उनकी जान को भी जोखिम में जाने से बचाता है।

इस मौके पर केनव्यू (ओरसल निर्माता) के पंकज महाजन ने कहा कि वह डायरिया से होने वाली बच्चों की मौत को रोकने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पीएसआई इंडिया के साथ मिलकर 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम को संचालित करते हुए सरकार के स्टॉप डायरिया कैम्पेन में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अलीगंज के अधीक्षक डॉ. हेमंत कुमार ने अपने पूरे स्टाफ के साथ इस अभियान को सफल बनाने का भरोसा दिया। इस मौके पर पीएसआई इंडिया से समरेन्द्र बेहरा, अमित कुमार, पारुल सक्सेना, अनिल द्विवेदी, धर्मेन्द्र त्रिपाठी, विभीषन, प्रवीन कुमार आदि उपस्थित रहे।

गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश: भारत की प्रगति रोकने वाली ताकतों से सतर्क रहने का आह्वान, सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय एकता पर दिया जोर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रीराम कथा के विश्राम सत्र एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की प्रगति, सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जागरूकता को लेकर विस्तृत विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने तीव्र गति से विकास किया है और अगले दो-तीन वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की क्षमता रखता है। उन्होंने लोगों से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें भारत की प्रगति, सनातन संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश विरोधी गतिविधियों और षड्यंत्रों का समर्थन करते हैं। उन्होंने रामायण के कालनेमि प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान समय में भी ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि समाज ऐसे तत्वों से अनभिज्ञ रहेगा तो स्वयं अपने हितों को नुकसान पहुंचाएगा।उन्होंने कहा कि आज जब भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है, तब कुछ शक्तियां देश में अस्थिरता, अशांति और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय देश के 120 जिलों में नक्सलवाद सक्रिय था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ऐसे में जो ताकतें पहले नक्सलवाद को बढ़ावा देती थीं, वे अब नए और छद्म रूपों में सामने आने का प्रयास कर सकती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में जब भी देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ा, तब चुनौतियां भी सामने आईं। उन्होंने रामायण, महाभारत और प्राचीन भारत के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज को केवल उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि व्यवस्था को कमजोर करने वाली ताकतों के प्रति लगातार सजग रहना चाहिए।उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा सभी मतों और सम्प्रदायों का सम्मान और संरक्षण करती है, लेकिन कुछ लोग इस सांस्कृतिक धारा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से गुरु, शिक्षक और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे नई पीढ़ी को सही दिशा दें और समाज को विभाजित करने वाली प्रवृत्तियों से बचाएं।मुख्यमंत्री ने आधुनिक जीवनशैली और तकनीक के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को आवश्यकता से अधिक स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभिभावकों को स्वयं भी मोबाइल का सीमित उपयोग कर बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरह बंद करने का प्रयास किया जाए। उनके अनुसार, बच्चों द्वारा प्रतिदिन कई घंटे मोबाइल पर बिताने से उनकी आंखों, मानसिक क्षमता और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व भारतीय गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि गुरु केवल दीक्षा देने वाला व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि माता-पिता, बड़े भाई-बहन, शिक्षक और जीवन में मार्गदर्शन देने वाला प्रत्येक व्यक्ति गुरु की भूमिका निभाता है। समाज और राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान भी इन्हीं मूल्यों से संभव है।मुख्यमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा, योग और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियों, ताम्रपत्रों, सिक्कों और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में प्राचीन पांडुलिपियां और ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, जिनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सदियों से विविधताओं के बावजूद एक राष्ट्र रहा है। उन्होंने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि जातीयता, क्षेत्रीयता और विभाजनकारी सोच से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अस्तित्व ही प्रत्येक नागरिक और समाज की शक्ति का आधार है तथा देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

सारनाथ से उपमुख्यमंत्री का संदेश: भगवान बुद्ध के विचार आज भी विश्व को शांति और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखा रहे हैं

लखनऊ। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान बुद्ध के करुणा, अहिंसा, शांति और मानव कल्याण के संदेश आज भी पूरी मानवता के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने हजारों वर्ष पहले थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता, संघर्ष और सामाजिक चुनौतियों के वर्तमान दौर में भगवान बुद्ध के कालजयी विचार विश्व को शांति, सद्भाव और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखा रहे हैं।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहा है। भगवान बुद्ध की करुणा, अहिंसा और शांति की अमर धरोहर को विश्वभर में नई ऊर्जा और सम्मान के साथ स्थापित किया जा रहा है।

हज-2027 के लिए सऊदी अरब में प्रतिनियुक्ति का अवसर, 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

लखनऊ। हज-2027 के सफल संचालन के लिए भारतीय कौंस्लावास, जद्दाह (सऊदी अरब) में अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष एवं महिला सरकारी कर्मचारियों से को-ऑर्डिनेटर (प्रशासन), हज अधिकारी तथा हज सुपरिटेंडेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 10 अगस्त, 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार को-ऑर्डिनेटर (प्रशासन) के पद के लिए अखिल भारतीय सेवा अथवा संगठित केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप 'ए' श्रेणी के ऐसे अधिकारी पात्र होंगे, जिनका वेतन ग्रेड लेवल-12 या 13 हो।

ई-सिम के सहारे विदेश से चल रहा था 'डिजिटल अरेस्ट' का खेल, लखनऊ साइबर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन ₹CYVAJRA₹ के तहत लखनऊ साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि भारतीय नागरिकों के पहचान दस्तावेजों और ई-केवाईसी का दुरुपयोग कर फर्जी ई-सिम तैयार किए जाते थे, जिन्हें कंबोडिया सहित विदेशों में सक्रिय साइबर अपराधियों को बेचा जाता था। इन ई-सिम के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट, निवेश धोखाधड़ी, ओटीपी फ्रॉड, ट्रेडिंग फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था। मामले में पुलिस ने 70 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए 35 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण, पुलिस उपायुक्त (अपराध) अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) किरन यादव के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।पुलिस के अनुसार पीड़ित को फोन कर खुद को एटीएस पुणे का अधिकारी बताया गया और मनी लॉन्ड्रिंग सहित गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर 16 जुलाई से 22 जुलाई तक लगातार वीडियो कॉल के माध्यम से मानसिक दबाव बनाया गया। तथाकथित ₹डिजिटल अरेस्ट₹ में रखकर पीड़ित को अपनी बैंक जमा राशि और एफडी विभिन्न खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। भय और दबाव में आकर पीड़ित ने कुल 70 लाख रुपये चार अलग-अलग बैंक खातों में भेज दिए। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन बैंक खातों में जमा 35 लाख रुपये फ्रीज करा दिए।विवेचना के दौरान तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जिस मोबाइल नंबर से पहली कॉल की गई थी, उसकी जांच की गई। पता चला कि संबंधित सिम लखनऊ के एक अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल से जारी किया गया था। जब सिम धारक का सत्यापन किया गया तो वह बेहद सामान्य और गरीब व्यक्ति निकला, जिसे यह तक जानकारी नहीं थी कि उसके नाम पर जारी सिम का उपयोग अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध में किया जा रहा है।जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी सुमित कुमार रावत अधिकृत जियो सिम विक्रेता था। उसका संपर्क एयरटेल सेवा प्रदाता ईशु यादव से था, जिसने उसे बड़ी संख्या में ब्लैंक एयरटेल सिम उपलब्ध कराए थे। सुमित नया जियो सिम लेने या मोबाइल नंबर पोर्ट कराने आने वाले ग्राहकों से तकनीकी समस्या का बहाना बनाकर दो बार ई-केवाईसी कराता था।

सारनाथ में धम्मचक्क पवत्तन दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज से, देश-विदेश के बौद्ध विद्वान करेंगे मंथन

लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश तथा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, सारनाथ के संयुक्त तत्वावधान में 29 और 30 जुलाई को सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार में ₹धम्मचक्क पवत्तन दिवस का महत्व₹ विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में देश-विदेश के बौद्ध विद्वान, भिक्षु, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश तथा बौद्ध दर्शन के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श करेंगे।संगोष्ठी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, सारनाथ के प्रभारी वेन आर. सुमित्थानन्द थेरो करेंगे।

संक्षेप

उधार के रुपये के विवाद ने ली युवक की जान, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र में उधार के रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब चार माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मो. मुस्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वंसथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बिजनौर कपिल गौतम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, 11 मार्च 2026 को सीमा यादव ने बिजनौर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति विजय कुमार यादव ने कुछ लोगों को रुपये उधार दिए थे। जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

सारनाथ की वैश्विक पहचान पर उप मुख्यमंत्री का गौरव, बोले- भगवान बुद्ध के विचार आज भी विश्व को दिखा रहे शांति का मार्ग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध का करुणा, अहिंसा, शांति और मानव कल्याण का संदेश आज भी पूरी मानवता के लिए उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों वर्ष पहले था। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों और अस्थिरता का सामना कर रहा है, तब भगवान बुद्ध के विचार मानव समाज को शांति, सद्भाव और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखा रहे हैं।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहा है। भगवान बुद्ध की करुणा, अहिंसा और शांति की अमूल्य धरोहर को विश्व समुदाय तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को व्यवहार में उतारते हुए विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान बुद्ध की प्रथम धम्मदेशना स्थली सारनाथ का यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होना भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

गोशालाओं के बीच होगी उत्कृष्टता की प्रतियोगिता, आत्मनिर्भर और उत्पादक केंद्रों के रूप में विकसित करने की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण को नई दिशा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने गोशालाओं को व्यवस्थित, उत्कृष्ट, आत्मनिर्भर और उत्पादक केंद्रों के रूप में विकसित करने की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में आयोग की बैठक में गोशालाओं के समग्र विकास, वैज्ञानिक प्रबंधन और किसानों को गो-आधारित प्राकृतिक खेती से जोड़ने को लेकर विस्तृत मंथन किया गया।बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, उपाध्यक्ष अतुल सिंह और महेश शुक्ल तथा सदस्य राजेश सिंह सेंगर, रमाकांत उपाध्याय और दीपक गोयल ने गोशालाओं की कार्यप्रणाली में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की।बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद की गोशालाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विशेष मूल्यांकन एवं प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मूल्यांकन में गोशालाओं की स्वच्छता, वैज्ञानिक प्रबंधन, गोवंश के स्वास्थ्य एवं पोषण, नस्ल संवर्धन, दुग्ध उत्पादन, जनसहभागिता तथा आत्मनिर्भरता के प्रयासों को प्रमुख आधार बनाया जाएगा

पेपर लीक पर मायावती का सरकार पर निशाना, कहा- केवल सख्त कानून से नहीं, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार से रुकेगा अपराध

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष Mayawati ने पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल कड़े कानून बनाने से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और अपराध को होने से पहले रोकने की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।मायावती ने सोशल मीडिया पर जारी अपने विस्तृत बयान में कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित होता है और कई मामलों में युवा आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पेपर लीक से संबंधित सख्त दंड का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया गया है, लेकिन लोगों के मन में यह आशंका बनी हुई है कि क्या केवल कानून से इस समस्या का समाधान संभव होगा।उन्होंने कहा कि नया कानून भी अपराध होने के बाद सजा का प्रावधान करता है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता अपराध को होने से पहले रोकने की है। उनके अनुसार, अपराध नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था के बिना ऐसे कानून अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पहले से मौजूद कानून भी इस दिशा में प्रभावी साबित नहीं हुए हैं।

बसपा प्रमुख ने कहा कि पेपर लीक केवल शिक्षा व्यवस्था की एक समस्या है, जबकि शिक्षा तंत्र की चुनौतियां इससे कहीं अधिक व्यापक और गंभीर हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए दिए जाने वाले ऋण को सस्ता और कल्याणकारी बनाने, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा पूरी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि इससे गरीब, वंचित और मेहनतकश परिवारों के बच्चों को समान अवसर मिल सकेंगे, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है।मायावती ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में सक्षम होते हैं, जबकि लाखों प्रतिभाशाली गरीब छात्र संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता को दूर किए बिना केवल पेपर लीक पर कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा।उन्होंने संसद में हुई चर्चा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर बहस के दौरान अधिकांश राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ सके। उनके अनुसार, गंभीर विमर्श की अपेक्षा आरोप-प्रत्यारोप अधिक देखने को मिला, जिससे लोगों के मन में नए कानून की प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के सैरपुर थाना क्षेत्र से लापता हुई 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को किशोरी की मां ने सैरपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की।26 जुलाई को सैरपुर पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। इसके बाद साक्ष्य संकलन और पूछताछ के दौरान मामले में गोविन्द पाल और हिमांशु यादव के नाम सामने आए। जांच में अपहरण और दुष्कर्म सहित पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की पुष्टि होने पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं।घटना के खुलासे के बाद पुलिस टीम लगातार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गोविन्द पाल फर्रुखाबाद मोड़ के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोविन्द पाल (21 वर्ष) निवासी ज्वारगांव, थाना सैरपुर, लखनऊ के रूप में हुई है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में फरार दूसरे आरोपी हिमांशु यादव की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

आखिर कौन है यूपी में नकल संस्कृति का जनक

आज के दौर में जबकि पेपर लीक जैसी घटनाओं के संबंध में निर्णायक प्रक्रिया तय की जा रही हो तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के नौजवानों के मन में यह प्रश्न भी है कि आखिर नकल संस्कृति की जड़ें कहां से शुरू हुईं और किस शासनकाल में पल्लवित पुष्पित होते हुए इतनी बड़ी बेल बन गईं। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इस राज्य के अधिसंख्य युवा परीक्षाओं में अपना भविष्य देखते हैं और जब उनकी मेधा को उचित मंच नहीं मिल पाता तो वह हताशा में चले जाते हैं। प्रदेश के युवाओं का भविष्य परीक्षा कक्ष का माहौल और भर्ती बोर्ड की नीयत से तय होता है। बीते तीन दशकों में इस राज्य ने इस मोर्चे पर दो बिल्कुल विपरीत स्थितियां देखी हैं। एक समय समाजवादी पार्टी की सरकारों का दौर भी देखा जब नकल को लगभग संस्थागत छत्रछाया मिली हुई थी और भर्तियों में खुलेआम भाई-भतीजावाद चलता था। दूसरा दौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का है, जब नकल माफिया की जड़ों पर देश का सबसे कठोर कानून बनाकर प्रहार किया गया। इन दोनों दौर की तुलनात्मक बात इसलिए कि यह उन लाखों युवाओं की सांसों से जुड़ा सवाल है, जिनकी आने वाली ज़िंदगी एक परीक्षा के परिणाम पर टिकी होती है।

किसी भी सरकार का चरित्र उसके फैसलों से तय होता है। बात शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। 1992 से शुरू करते हैं जब उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाना था। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव की सरकार सत्ता में आई, इस कानून को व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी बना दिया गया। इसके साथ ही स्व-केंद्र यानी सेल्फ-सेंटर की नीति को बनाए रखा गया, जिसके तहत विद्यार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकते थे। यह नीति देखने में एक प्रशासनिक फैसला भर लगती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक साबित हुए। इस नीति की आड़ में राज्यभर में एक समानांतर तंत्र खड़ा हो गया, जिसे बाद में लोग नकल माफिया के नाम से जानने लगे। इस ढील का सीधा असर परीक्षा परिणामों पर भी दिखा। वर्ष 2004 में इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अचानक बेतहाशा ऊंचाई तक पहुंच गया, जो किसी भी सामान्य शैक्षणिक प्रगति के बजाय व्यवस्थागत ढील का ही परिणाम प्रतीत होता था। इसका सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जो छात्र वर्षों मेहनत करके योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते थे, वे इस भीड़ में कहीं पीछे छूट गए, जबकि माफिया तंत्र की जेबें भरती रहीं। शिक्षा की नींव में यह खोखलापन आने वाले वर्षों तक राज्य को नुकसान पहुंचाता रहा।

समाजवादी पार्टी की ही सत्ता जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी तो उम्मीद थी कि भर्तियों को लेकर कुछ सार्थक फैसले लिए जाएंगे लेकिन 2012 से 2017 के बीच, स्थिति में सुधार आने के बजाय समस्या और गहरी होती चली गई। इस दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की गरिमा को बार-बार आघात पहुंचा। राज्य का शायद ही कोई बड़ा भर्ती बोर्ड ऐसा बचा हो, जिस पर धांधली या पेपर लीक के आरोप न लगे हों। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र ट्रेजरी से लीक होने की घटना ने लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को झटका दिया और अंततः परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसी तरह प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा का पर्चा भी सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो गया, जिसके बाद भारी विरोध और हंगामे के बीच परीक्षा को रद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया में भी स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें सत्ताधारी दल से जुड़े प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता के दावे सामने आए। नकल और पेपर लीक उस दौर की एक व्यवस्थागत विशेषता के रूप में उभरकर सामने आए।

यहां एक और गौरतलब बात यह है कि प्रदेश में जहां तमाम सरकारी विभागों की भर्तियां उप्र लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थीं, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान अपने सभी विभागों में सारी भर्तियां खुद करते थे। उनके विभागों में तब धर्म विशेष के लोगों को जमकर नौकरियां बांटी गईं। भर्तियों में भाई-भतीजावाद सपा दौर की विशेष पहचान बना। उप्र लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जिसकी निष्पक्षता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, उस पर भी गंभीर सवाल उठे। एक विशेष जाति-वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन में असंगत बहुलता को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका तक दायर की गई, जिसमें चयन प्रक्रिया में भारी असंतुलन के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। ऐसे आरोपों ने मेधावी और अन्य वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश पैदा किया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि योग्यता से ज़्यादा जाति और राजनीतिक निकटता ही चयन का आधार बन गई है। इसी कड़ी में पुलिस भर्ती को लेकर हुआ विवाद भी कम गंभीर नहीं था। हज़ारों सिपाहियों और पीएसी जवानों की भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े, राजनीतिक सिफारिशों और रिश्वतखोरी के प्रमाण मिलने के बाद सरकार को एक जांच समिति गठित करनी पड़ी, जिसकी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

छात्रों और युवाओं को भरोसा बना

पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन की जिन तस्वीरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देश का युवा खास कर 'जेन जी' केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है

एस. सुनील

प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की जो पहल की है उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के बाहर सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। उन्होंने जो नियम बनाने और विधायी कदम उठाने की पहल की है और युवाओं से सीधी अपील की है उसका असर यह हुआ है कि आंदोलन की नैतिक ताकत बने सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके साथ ही आंदोलन की तीव्रता काफी कम हो गई। इसकी व्यापकता भी धीरे धीरे कम हो रही है।

पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन की जिन तस्वीरों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देश का युवा खास कर 'जेन जी' केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया है वह देश की प्रतिनिधि तस्वीर नहीं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उन तस्वीरों से देश की वास्तविकता नहीं जाहिर हो रही है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेपर लीक की घटना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वंय कहा, 'जघन्य पाप' है। लेकिन आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर भी किसी को संदेह नहीं है। देश का युवा वर्ग और छात्रों का भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सीधा जुड़ाव या संवाद है कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री की गंभीरता को समझ रहे हैं। तभी गुरुवार, 23 जुलाई की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सीधे युवाओं को 'फ्रेंड्स' कह कर संबोधित किया। अपने मोबाइल से वीडियो बना कर उन्होंने पोस्ट किया और अगले दिन यानी शुक्रवार की रात को बताया कि उस पर कितनी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। गुरुवार रात के प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम वीडियो ने रिकॉर्ड बनाया। करीब 35 करोड़ लोगों ने उसे देखा और पेपर लीक से लेकर परीक्षा में सुधार के अनेक सकारात्मक सुझाव दिए, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने अगले वीडियो में किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की जो पहल की है उस पर छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के बाहर सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। उन्होंने जो नियम बनाने और विधायी कदम उठाने की पहल की है और युवाओं से सीधी अपील की है उसका असर यह हुआ है कि आंदोलन की नैतिक ताकत बने सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके साथ ही आंदोलन की तीव्रता काफी कम हो गई। इसकी व्यापकता भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका कारण यह है कि देश के युवाओं को अपने प्रधानमंत्री और उनके संकल्पों पर भरोसा है। उनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनको दूर किया जाएगा।

बहरहाल, पेपर लीक को लेकर भी प्रधानमंत्री की पहल पर एक साथ कई काम शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक संसद भवन के अंदर हुई, जिसमें द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब सरकार पेपर लीक और परीक्षा में अक्सर होने वाली दूसरी गड़बिड़यों को रोकने के लिए ज्यादा सख्त कानून बनाने जा रही है। इसे मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के शुरू में ही पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा करा कर कानून बनाया जाए। इसमें पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक की घटना की जांच दो महीने में होगी और तीन महीने के अंदर अदालत में ट्रायल पूरा करके फैसला सुनाया जाएगा। इस संशोधन बिल को मंजूरी देने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश दे दिया था। इस बिल में इस पूरी प्रक्रिया को वैधानिक स्वरूप देने का प्रावधान भी किया गया है।

इस मामले में सरकार की गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है। सरकार एनटीए का भी पुनर्गठन करने वाली है ताकि परीक्षा की प्रक्रिया को किसी भी तरह की लीक और गड़बड़ी से सुरक्षित किया जा सके। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वंय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं इसलिए युवाओं को और उनके अभिभावकों को भी भरोसा बना है। उनको लग रहा है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। ध्यान रहे पहले ही इस बात की घोषणा हो चुकी है कि अगले साल नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इससे भी छात्रों और युवाओं को भरोसा बना है।

दूसरी ओर अगर विपक्षी पार्टियों का रवैया देखें तो वह बहुत निराशाजनक दिखेगा। उनकी तरफ से किसी तरह का रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी ओर से सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जिस समय जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने इंतजार किया कि संसद का सत्र शुरू हो और मीडिया का अटेंशन बने तो वे आंदोलन शुरू करें। छात्रों व युवाओं के संसद मार्च से जो माहौल बना उसका लाभ लेने के लिए वे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। असल में उनको यह असुरक्षा बोध घेरे हुए था कि कहीं जंतर मंतर के प्रदर्शन को ज्यादा लोगों का समर्थन न मिल जाए या उसमें शामिल लोग विपक्ष की जगह न ले लें। इसलिए उन्होंने आनन फानन में प्रदर्शन किया और संसद की कार्यवाही पूरी तरह से ठप्प की।

सवाल है कि क्या देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास पेपर लीक की घटना का विरोध करने का नैतिक आधार है? अकेले राजस्थान में 2018 से 2023 के कांग्रेस राज में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और कांग्रेस की सरकार ने किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की। कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में भी अनेक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उसे रोकने या उसमें शामिल लोगों को सजा दिलाने में विफल रही कांग्रेस नीट यूजी के पेपर लीक के हवाले केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। वास्तविकता यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में कांग्रेस की केंद्र और राज्यों की सरकारों के मुकाबले बहुत बेहतर है। कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में एनडीए की सरकार बनने से पहले के सात साल में यूपीए के शासन में 71 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। असल में मौजूदा सरकार पिछली सरकार से जो गड़बड़ियां विरासत में मिली हैं उसे ठीक करने का काम कर रही है। इस काम में सरकार का सहयोग करने की बजाय विपक्ष इसमें अड़ंगा लगा रहा है।

विपक्ष के साथ एक संकट यह भी है कि उसकी पार्टियों में आपस में ही तालमेल नहीं है। हर पार्टी अपने हिसाब से राजनीति करने में लगी है। आम आदमी पार्टी को चूंकि अगले साल के चुनाव में पंजाब और गोवा में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है इसलिए वह कांग्रेस की पोल खोल रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियां चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या शरद पवार की एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे की शिव सेना, इनका सारा समय संतुलन बनाने में जा रहा है। ये कांग्रेस के साथ भी दिख रहे हैं और जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के समर्थन से चल रहे आंदोलन में भी दिख रहे हैं। सवाल है कि ऐसा विपक्ष कैसे युवाओं में भरोसा पैदा कर पाएगा कि वह उनके हित में काम कर रहा है?

व्यंग्य

बहस से ज्यादा अपेक्षा टकराव

विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का आज क्या औचित्य रह गया है? अगर ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े और संसद के बीच क्या फर्क रह जाएगा?

मानसून सत्र की शुरुआत के साथ संसद का नज़ारा कुछ बदला नजर आएगा। यह संभवतः पहला मौका है, जब बिना चुनाव हुए सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के संख्या बल में गुणात्मक बदलाव हुआ दिखेगा। बजट सत्र के बाद तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) बड़ी टूट-फूट हो चुकी है, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। इससे बिना नया जनादेश आए ही सत्ताधारी एनडीए मजबूत हो गया है। इस हद तक कि अभी दो महीने पहले लोकसभा सीटों के परिसीमन के मकसद से लाया गया जो विधेयक गिर गया था, सत्ता पक्ष उसे फिर से लाने की तैयारी में दिखा है।

इसी तरह विवादास्पद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025 और गिरफ्तारी होने पर 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री/ मंत्री पद खत्म करने का प्रावधान करने वाले विधेयक को भी लाने की चर्चा थी (जिसका इरादा शायद टाल दिया है)। पिछले सत्र तक इन विधेयकों के पारित होने की संभावना बेहद कमजोर थी। अभी भी इनके लिए सरकार संख्या बल का पूरा इंतजाम नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ और जोड़-तोड़ में कामयाब रही, तो इनके पारित होने की संभावना बन सकती है। मगर यही समस्या है। वह संभावना 2024 में आए जनादेश की भावना के विपरीत होगी। मुद्दा है कि दांव-पेच से जनादेश की भावना को इस तरह धता बताने का चलन आम हो जाता है, तो फिर विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, चुनाव घोषणापत्र आदि का क्या औचित्य रह जाएगा?

ये राजनीति के प्रेरक तत्व ना रहें, तो फिर पहलवानी के अखाड़े में होने वाली जोर-आजमाईश और संसदीय प्रक्रियाओं के बीच क्या फर्क रहेगा? क्या उसके बाद भी संसद को बहस के जरिए अधिकतम संभव सहमति निर्माण का मंच माना जा सकेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में इन प्रश्नों के उत्तर लगातार नकारात्मक होते गए हैं। संसद शोर, हंगामे, वॉकआउट, बहिष्कार, और कई बार तो शारीरिक बल के जरिए झड़पों का स्थल बनती चली गई है। नतीजतन, अधिवेशनों से पहले गंभीर बहस से ज्यादा अपेक्षा टकराव और तू तू-मैं- मैं की रहने लगी है। मानसून सत्र के पहले भी राजनीतिक क्षितिज पर यही माहौल हावी नजर आया है।

ब्लॉग

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन: अस्तित्व पर मंडराता खतरा

ललित गर्ग

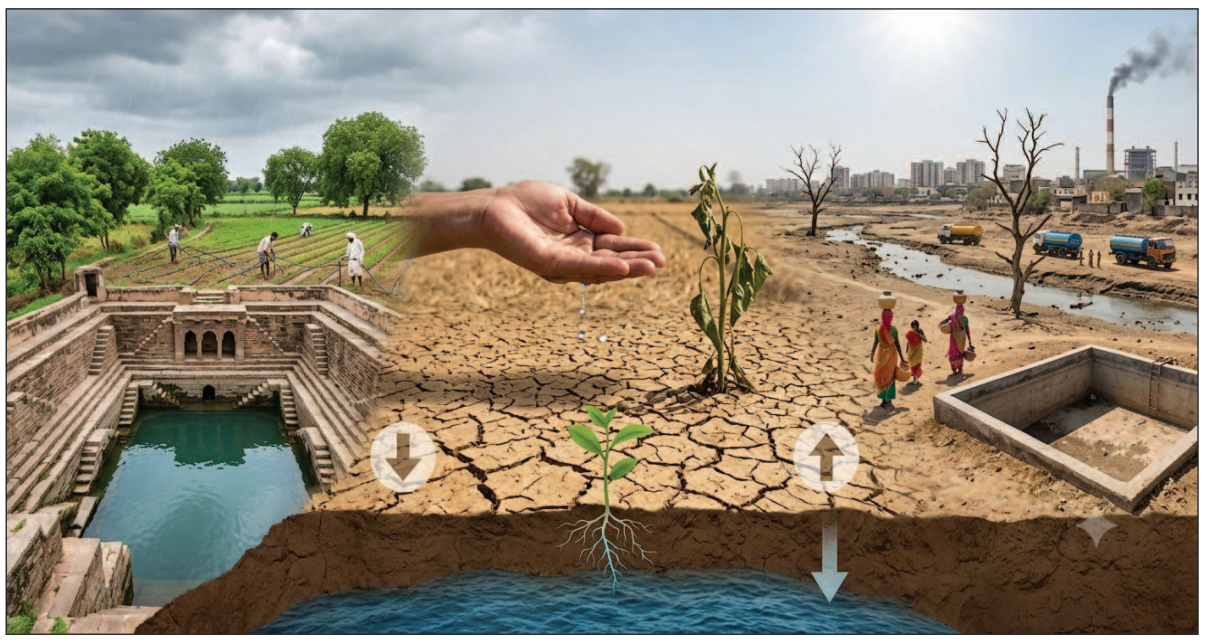

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है।

इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है।

भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया।

जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके।

भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि 'जल बचाना ही भविष्य बचाना है।' हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विवशता बन जाएगा।

राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव बने जगदीश आफले, 2 सितंबर को नियुक्ति पर लगेगी औपचारिक मुहर

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना नया सचिव चुन लिया है। पेशे से इंजीनियर और मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले को पहला सचिव बनाया गया है। CEO की नियुक्ति में देरी को देखते हुए ट्रस्ट ने सचिव के रूप में नया पद बनाया और आफले को यह जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को लगेगी, जब ट्रस्ट की अगली बैठक होगी।

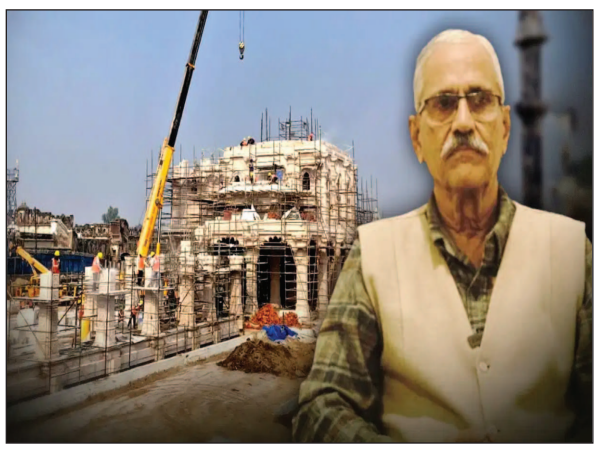

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जगदीश आफले को ट्रस्ट का नया अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को भी भेज दिया गया है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था और लंबे कयासबाजी के बाद महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था।

फिर 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में तत्कालीन महासचिव चंपत और ट्रस्टी अनिल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। साथ में ट्रस्ट ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में भी बदलाव करने का फैसला लिया। इसे देखते हुए ट्रस्ट की ओर से अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और जगदीश आफले का नाम बैंक भेजा गया, लेकिन बैंक ने आफले के ट्रस्टी नहीं होने पर सवाल किया था, जिससे खाता संचालन में गतिरोध आ गया था। लेकिन नई नियुक्ति के बाद ट्रस्ट में हस्ताक्षरकर्ता को लेकर बना गतिरोध अब खत्म हो गया है। वहीं एसबीआई ने भी नए प्रस्ताव आने के बाद खातों का संचालन फिर शुरू कर दिया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने की वजह से ट्रस्ट से जुड़े करीब एक हजार कर्मचारियों के वेतन और एजेंसियों के भुगतान पर असर पड़ रहा था।

बिना वेतन के ही प्रोजेक्ट मैनेजर रहे आफले

राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट मैनेजर रहे जगदीश आफले बिना वेतन के ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हें ट्रस्ट का पहला सचिव बनाया गया है। सचिव के अलावा ट्रस्ट के प्रवक्ता को लेकर चयन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए कई नामों पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि जल्द ही उसके लिए भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे से नाता रखने वाले जगदीश आफले बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े रहे हैं। वह पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वह पहले से ही अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू होने पर बिना वेतन ही प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल ली थी।

मुंबई IIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

आफले ने आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और फिर एमटेक किया। इसके बाद वह कई मल्टीनेशनल कंपनियों (MNC) से जुड़े। यही नहीं वह यूरोप के कुछ देशों के अलावा अमेरिका में भी काम करने गए। फिर वह भारत आ गए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने पर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अपनी सेवा देने लगे। वह अपनी पत्नी के साथ यहीं तीर्थ क्षेत्र भवन में रहते हैं।

सचिव के रूप में आफले की नियुक्ति के बाद अब ट्रस्ट की कार्यकारिणी को मुख्य कार्यकारी (सीईओ) और प्रवक्ता की नियुक्ति करनी है। फिलहाल प्रवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और जल्द ही नाम का ऐलान हो सकता है।

सीईओ के चयन पर अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि सीईओ के चयन में अभी वक्त लगेगा, इसलिए सचिव का नया पद बनाया गया है।

संक्षेप

जेल में कैदी की हालत बिगड़ी, दम तोड़ा

जौनपुर । जिला कारागार में बीते 5 वर्षों से बंद एक कैदी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन-फानन में जेल प्रशासन द्वारा उसे नजदीकी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतक कैदी की पहचान दया राम यादव 85 वर्ष ग्राम असरफगढ़ थाना खुटहनके रूप में हुई है, जो पिछले 5 वर्षों से हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। जेल प्रशासन के अनुसार, कैदी को अचानक सांस लेने में तकलीफ सीने में दर्द की शिकायत हुई थी।घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं, जेल में कैदी की मौत के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का सटीक पता चल सकेगा।

अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

जौनपुर। अनुसूचित जाति के युवक एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, में 100 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण षहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इसमें केवल 30 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। राजकीय फल संरक्षण केंद्र के प्रभारी जटाशंकर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अचार, जैम, जेली और मुरब्बा बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, लघु स्वसेजमार उद्योग स्थापित करने संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों को जनपद एवं मंडल में संचालित संबंधित उद्योगों का भ्रमण भी कराया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी राजकीय फल संरक्षण केंद्र, पॉलिटेक्निक चैराहा के बगल, कृषि कैंपस के अंदर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

अल्ट्रासाउंड जांच बंद होने से मरीज हलकान

जौनपुर। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा अचानक ठप होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण जांच कार्य फिलहाल बंद कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड न हो पाने से गर्भवती महिलाओं सहित विभिन्न रोगों से पीड़ति मरीजों को बिना जांच के वापस लौटना पड़ रहा है। कई मरीजों को मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है।अस्पताल प्रशासन के अनुसार मशीन में आई तकनीकी खराबी को दूर कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. संजय कन्नौजिया ने बताया कि मशीन को जल्द से जल्द ठीक कराकर अल्ट्रासाउंड सेवा पुनः शुरू कराई जाएगी, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

शिष्यों ने लिए गुरु मंत्र , गुरु के पांव पखारे

जौनपुर। शीतला धाम चैकिया माता श्री आश्रम पर पंडित सीताराम नाम शरण जी महाराज के गुरु पूजन महोत्सव में पहले गुरु के पांव धुल कर माथे लगाए और तिलक लगाकर माला पहनाकर शीश झुकाए इस मौके पर सभी शिष्यों में भजन कीर्तन भी सुनाएं और गुरु पूर्णिमा पर सभी शिष्य ने आशीर्वाद लिया और एक सौ दस शिष्यों ने गुरु मंत्र लिया और कहा बिन गुरु ज्ञान कहां से होई । पुजे पांव दिखे सब कोई । इस मौके पर जनकपुर नेपाल आजमगढ़ प्रतापगढ़ सुल्तानपुर वाराणसी जौनपुर सदर चैकिया धाम के सभी शिष्यों ने जयकारा लगाया । इस मौके पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव पंडित सीताराम नाम शरण जी महाराज का माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया वही शीतला धाम चैकिया मंदिर के महंत विवेकानंद पंडा जी महाराज भी स्वागत किए । अजय त्रिपाठी चंद्रशेखर आजाद कृपा शंकर पाठक सुरेंद्र सिंह लाल बाबा अरविंद महंत सुरेश पांडे चंद्रकला सखी विमल सखी पार्वती सखी शुभांगा जानकी सखी गुड्डू पांडा पवन त्रिपाठी राहुल त्रिपाठी बैकुंठ चैबे राहुल चतुर्वेदी आदि सभी शिष्य मौजूद रहे।

'Site is Hacked' एडमिशन नहीं मिला तो IIT कानपुर की वेबसाइट हैक करने का दावा, अब छात्र का दोबारा होगा स्किल टेस्ट

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिला न मिलने से निराश एक छात्र ने अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। छात्र ने IIT कानपुर की वेबसाइट हैक करने का दावा करते हुए उस पर 'Site is Hacked, All I Need Is Just a Fair Chance' लिख दिया। इसके बाद कथित हैकिंग के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Reddit पर भी साझा किए गए। छात्र ने साफ किया कि उसका मकसद संस्थान को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक मौका चाहता था। छात्र ने वेबसाइट पर कथित रूप से संदेश लिखने के बाद उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पोस्ट में उसने लिखा कि वह IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिला चाहता था, लेकिन चयन नहीं हो सका। उसका कहना था कि उसे अपनी तकनीकी क्षमता साबित करने का उचित अवसर नहीं मिला, इसलिए उसने यह कदम उठाया। हालांकि, छात्र ने अपने संदेश में यह भी कहा कि उसका उद्देश्य वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना या किसी तरह का डेटा चुराना नहीं था।

वेबसाइट हैक होने के दावे के बाद IIT कानपुर के छात्रों और प्रोफेसरों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही संस्थान के अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। शुरुआती स्तर पर छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर भी विचार किया गया। हालांकि, बाद में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने मामले को अलग नजरिए से देखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यदि छात्र वास्तव में इतनी तकनीकी क्षमता रखता है, तो उसकी योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

दोबारा होगा स्किल टेस्ट

प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के अनुसार, साइबर सिक्योरिटी कोर्स में प्रवेश के दौरान सभी उम्मीदवारों को हैकथॉन और तकनीकी परीक्षण के माध्यम से अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया गया था। उस समय संबंधित छात्र प्रदर्शन नहीं कर पाया था। अब, वेबसाइट हैक करने के दावे के बाद संस्थान उसकी तकनीकी योग्यता का दोबारा टेस्ट लेगा। यदि छात्र निर्धारित टेस्ट में सफल होता है, तो उसे संस्थान में आगे अवसर देने पर विचार किया जाएगा।

पहले भी प्रतिभा को मिला है सम्मान

IIT कानपुर पहले भी असाधारण साइबर प्रतिभाओं को अवसर देता रहा है। इससे पहले सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल में सुरक्षा संबंधी खामी की जानकारी देने वाले एक प्रतिभाशाली छात्र की तकनीकी क्षमता को देखते हुए संस्थान ने उसे अपनी C3iHub साइबर सिक्योरिटी लैब में काम करने का मौका दिया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए IIT कानपुर अब इस छात्र के दावे की भी निष्पक्ष जांच करेगा। फिलहाल संस्थान की ओर से छात्र की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने की तैयारी की जा रही है। यदि वह अपनी योग्यता साबित कर देता है, तो उसके लिए IIT कानपुर के दरवाजे खुल सकते हैं।

विश्व ओआरएस दिवस पर डायरिया चैम्पियन को किया सम्मानित

आर्यावर्त संवाददाता

सीतापुर। विश्व ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) दिवस पर बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.आर. समद्दर ने कहा कि ओआरएस के लाभ और उपयोग के बारे में आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर बताएं, तभी विश्व ओआरएस दिवस मनाना सार्थक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के लिए ओआरएस के प्रति भी जागरूकता जरूरी है।

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डायरिया को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले चैंपियन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में डॉ. कमलेश कुमार- अधीक्षक मछरेहटा, डॉ. दीपांशु शुक्ला-अधीक्षक महोली, देश दीपक त्रिपाठी फार्मासिस्ट कॉर्पोरेशन स्टोर, आफताब -फार्मासिस्ट मुंशीगंज, सदर की आशा कार्यकर्ता

बबली देवी शामिल रहीं। इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार त्रिपाठी- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्टाप डायरिया अभियान के दौरान घर-घर ओआरएस की उपलब्धता पर जोर दिया । मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि डायरिया के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार वाहन गांव और शहर में पहुँच रहे हैं। प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर समुदाय को शून्य से पांच साल तक के बच्चों में डायरिया के लक्षण, कारण और बचाव आदि के बारे में जागरूक कर रहे हैं।

इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपेन्द्र कुमार शुक्ला ने कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के लिए जनजागरूकता बहुत जरूरी है। डॉ. अनिल कुमार त्रिपाठी -अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि डायरिया रोको अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू भी "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के माध्यम से सराहनीय सहयोग कर रहे हैं। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के. एन. मिश्रा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि बारिश और उमस में बच्चा डायरिया की चपेट में कई कारणों से आ सकता है, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, खुले में शौच करने या बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें। डायरिया का सही इलाज ओआरएस का घोल और जिंक के टेबलेट हैं, जिन्हें उम्र के अनुसार निश्चित अवधि तक जरूर दें। उन्होंने कहा कि बच्चे को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार पतली दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए।

इस मौके पर डॉ. पीयूष रंजन एसएमओ डब्ल्यूएचओ, डॉ. राहिल फरीद, डॉ. शानू कुमार वर्मा, डॉ. विवेक कनौजिया, डॉ. अनूप श्रीवास्तव, आईसीडीएस प्रभारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी कमलेश कुमारी, पीएसआई इंडिया से कमलेश कुमार, अश्विनी मिश्रा और आलोक कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।

राजमार्ग पर गो वंश से हो रही दुर्घटनाएं

जौनपुर। मछलीशहर -वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों आवारा पशुओं के लिए विश्राम स्थल बन गया है। जंघई और मछलीशहर के बीच पड़ने वाले बंधवा बाजार, तिलौरा बाजार, गोधना, मोलनापुर बाजारों के आस-पास छुट्टा गो वंश खेतों में घास चरकर सुबह-शाम इसी सड़क के किनारे या बीचों-बीच बैठकर आराम से जुगाली करते आपको दिख जायेंगे।आये दिन इन गो वंशों और इंसानो की भिड़ंत भी होती रहती है कभी ये बेजुबान तो कभी इंसान इस भिड़ंत में अपनी जान गंवाते या फिर टूट फूट का शिकार बनते हैं। बारिश के दिनों में खेतों में कीचड़ होने के कारण ये जानवर अपने आराम के लिए सड़क को अधिक सुविधाजनक महसूस करते हैं। इसमें काले रंग के गो वंश तो रात में बिल्कुल पास आने पर दिखते हैं, तेज रफ्तार चल रहे लोगों को सम्हलने का मौका नहीं मिलता है और उनकी टकराहट इन गो वंशों से हो जाती है।

गाजियाबाद में सड़क हादसा, नई बोलेरो लेकर हरिद्वार जा रहे थेतभी ट्रक से भीषण टक्कर, 3 की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा निवाड़ी थाना क्षेत्र में उस समय हुआ, जब हरिद्वार दर्शन के लिए जा रही एक बोलेरो की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 12:30 बजे निवाड़ी थाना क्षेत्र में ट्रक और बोलेरो पिकअप की टक्कर की सूचना कंट्रोल रूम को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में तीन

लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जांच में सामने आया है कि बोलेरो हाल ही में खरीदी गई थी। वाहन मालिक अपने परिवार और परिचितों के साथ नई गाड़ी को हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान और धार्मिक दर्शन कराने जा रहे थे। इसी यात्रा के दौरान निवाड़ी क्षेत्र में सामने से आ रहे ट्रक से वाहन की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे ने श्रद्धालुओं की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया।

ट्रक चालक और कंडक्टर हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ट्रक चालक और कंडक्टर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वाहन की गति, सड़क की स्थिति और चालक की लापरवाही सहित अन्य बिंदुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आदर के साथ किया गुरूओं का पूजन

जौनपुर जिले भर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने आदर व सत्कार के साथ अपने गुरुओं का पूजन किया। जिसमें महर्षि वेद व्यास का स्मरण, चरण पादुका पूजन, और आशीर्वाद प्राप्ति जैसे मुख्य कार्य शामिल रहे। यह पर्व ज्ञान और अंधकार दूर करने वाले गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है । कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पांय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय.श जिस गुरु को गोविंद या यानि ईश्वर से भी ज्यादा मान-सम्मान दिया, उसी के सम्मान हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा या फिर कहें व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही तमाम तरह के ग्रंथों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था. । ज्ञात हो कि गुरुपूर्णिमा के दिन गुरुस्मरण करने पर शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होने में सहायता होती है ।

एक हफ्ते तक मॉनसून की झमाझम बारिश... UP सहित इन 20 राज्यों में भी बरसेंगे बादल

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 29 और 30 जुलाई के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 3 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

आईएमडी के अनुसार, 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 50

किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और पंजाब में 30 जुलाई से 3 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य और पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 29 जुलाई से अगले 4 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा में कुछ स्थानों पर 50 से 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत भी रहेगा बारिश की चपेट में

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कई इलाकों में भारी और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ और मराठवाड़ा में भी लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। इन क्षेत्रों में40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

दक्षिण भारत में भी सक्रिय रहेगा मानसून

दक्षिण भारत के केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी 3 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में गर्म और उमस भरे मौसम की स्थिति बनी रह सकती है।

मौसम विभाग ने मछुआरों और समुद्र में जाने वाले लोगों को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के आसपास तेज हवाओं को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। कुल मिलाकर आने वाले पांच दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और कई राज्यों में भारी बारिश जनजीवन को प्रभावित कर सकती है।

स्कूल वैन खाई में पलटी, एक दर्जन बच्चे घायल

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के बेलवार गांव में गुरुवार को सड़क हादसा हो गया। एस.एस. पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब 18 बच्चे सवार थे। दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।हादसे में 5 वर्षीय छात्र अभी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार पाण्डेय स्वयं सरकारी वाहन से बच्चे को बेहतर इलाज के लिए लेकर रवाना हुए। दुर्घटना में स्कूल की शिक्षिका संध्या यादव और छात्रा श्रेजा यादव भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों को जिला अस्पताल

रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने वैन के शीशे तोड़कर अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

जगह की कमी अब नहीं बनेगी रुकावट, कंटेनर में किचन गार्डनिंग कर उगाएं ये 6 सब्जियां

अगर आप भी जगह की कमी के कारण ताजी और बिना केमिकल वाली सब्जियां उगाने का अपना मन मार लेते हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है।

जरा सोचिए, सुबह-सुबह आप अपनी बालकनी का दरवाजा खोलें और ताजे लाल टमाटरों की चमक, धनिया की भीनी-भीनी महक और हरे-भरे पालक के पत्ते आपको देखने को मिलें। जी हां, खुद के हाथों से उगाई सब्जियों का स्वाद चखने के लिए आपको किसी बड़े खेत की नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटे से कोने की जरूरत है।

आपकी बालकनी में रखा एक पुराना प्लास्टिक का डिब्बा, घर की कोई बेकार बाल्टी या खिड़की पर रखा छोटा-सा गमला... बस यही काफी है आपके सपनों का 'किचन गार्डन' बनाने के लिए। आइए जानते हैं वो 6 शानदार सब्जियां जिन्हें आप कंटेनर में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं।

टमाटर

टमाटर के बिना तो हमारी रसोई अधूरी है। इसे गमले में उगाना सबसे आसान है। बस एक 10-12 इंच गहरा गमला लें, उसमें अच्छी उपजाऊ मिट्टी डालें और टमाटर के बीज या छोटा पौधा लगा दें। इन्हें अच्छी धूप की जरूरत होती है। जब आपके गमले में लाल-लाल, रसीले टमाटर उगेंगे, तो आपको जो खुशी मिलेगी, उसका कोई जवाब नहीं।

हरी मिर्च

तीखी और ताजा हरी मिर्च उगाने के लिए आपको बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। एक छोटे से कंटेनर या पुराने प्लास्टिक के डिब्बे में भी मिर्च का पौधा आराम से लग जाता है। बस इसे धूप वाली जगह पर रखें। घर की उगाई हुई ताज़ा मिर्च का स्वाद और उसकी खुशबू, बाजार की कई दिन पुरानी मिर्च से सौ गुना बेहतर होती है।

पालक

हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक सबसे जल्दी और आसानी से उगने वाली सब्जी है। इसके लिए आपको गहरे गमले की नहीं, बल्कि चौड़े मुंह वाले कंटेनर की जरूरत होती है। बस मिट्टी में बीज छिड़कें और हल्का पानी दें। कुछ ही हफ्तों में आपके पास ताजा पालक तैयार होगा, जिसे आप दाल, पनीर या पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं।

धनिया

सब्जी की गार्निशिंग हो या हरी चटनी, धनिया हर घर की जरूरत है। इसे उगाने के लिए आपको बाजार से बीज लाने की भी जरूरत नहीं है। रसोई में रखे साबुत धनिया के बीजों को हल्का सा दो टुकड़ों में तोड़ लें और गमले की मिट्टी में बिखेर दें। धनिया बहुत जल्दी उग आता है और यह आपके किचन गार्डन को बहुत ही सुंदर और खुशबूदार बना देता है।

बैंगन

शायद आपको लगे कि बैंगन के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक 12-14 इंच गहरे गमले में बैंगन का पौधा बहुत अच्छे से पनपता है। बस इसके पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पर रखें और नियमित रूप से पानी दें। कुछ ही समय में आपका पौधा गोल या लंबे बैंगनों से लद जाएगा।

मूली

सलाद की शान मूली को भी आप कंटेनर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए बस यह ध्यान रखें कि आपका गमला कम से कम 6-8 इंच गहरा हो, ताकि मूली को मिट्टी के नीचे बढ़ने की पूरी जगह मिल सके। मूली बहुत तेजी से बढ़ती है और बीज बोने के सिर्फ 30 से 40 दिन बाद ही आपको ताजी और कुरकुरी मूली खाने को मिल जाएगी।

कंटेनर गार्डनिंग शुरू करने से पहले इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखें:

मिट्टी हो शानदारः गमले की मिट्टी में कोकोपीट और जैविक खाद जरूर मिलाएं। इससे मिट्टी हल्की रहेगी और पौधों को बढ़ने की ताकत मिलेगी।

पानी निकलने की जगहः कंटेनर के नीचे छेद होना बहुत जरूरी है, ताकि फालतू पानी बाहर निकल सके। पानी रुकने से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं।

भरपूर धूपः सब्जियों वाले पौधों को दिन में कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप जरूर चाहिए।

शेविंग के बाद त्वचा पर हो जाते हैं लाल चकत्ते या दाने? न करें ये गलतियां

शेविंग एक आम प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल लोग शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए करते हैं। हालांकि, कई बार शेविंग के बाद त्वचा पर लाल चकत्ते या छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, जो काफी असुविधाजनक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें लोग शेविंग करते समय अनजाने में कर बैठते हैं और इनसे बचकर आप बिना किसी परेशानी के शेविंग कर सकते हैं।

पुराने शेवर का इस्तेमाल करना

कई लोग शेविंग के बाद शेवर को फेंक देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि, पुराने शेवर का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती है।

पुराने शेवर से शेव करने पर त्वचा पर कट लगने की संभावना बढ़ जाती है और इससे लाल चकत्ते या दाने हो सकते हैं।

इसलिए, हमेशा नए शेवर का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे और आपको कोई परेशानी न हो।

सूखी त्वचा पर शेविंग करना

गीली त्वचा पर शेविंग करने से बालों को हटाना आसान हो जाता है और इससे त्वचा पर कोई खरोंच या जलन नहीं होती।

इसलिए, हमेशा नहाने के बाद या नहाते समय ही शेव करें, क्योंकि इससे न केवल आपके बाल आसानी से हटेंगे, बल्कि आपकी त्वचा भी मुलायम और ताजगी भरी महसूस होगी।

इसके अलावा गीली त्वचा पर शेविंग करने से उस्तरा के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं से भी बचा जा सकता है।

शेविंग क्रीम का इस्तेमाल न करना

शेविंग क्रीम का इस्तेमाल न करने से त्वचा पर जलन या खुजली हो सकती है। शेविंग क्रीम या जेल आपके बालों को मुलायम बनाती है और उस्तरा को आसानी से चलाने में मदद करती है।

इससे आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहती है। अगर आप बिना शेविंग क्रीम के शेव करते हैं तो इसके कारण त्वचा पर लाल चकत्ते या दाने हो सकते हैं, जो काफी ज्यादा असुविधाजनक हो सकते हैं।

बहुत अधिक दबाव डालकर शेव करना

बहुत अधिक दबाव डालकर शेव करना भी एक बड़ी गलती है। कई लोग जल्दी-जल्दी बाल हटाने के चक्कर में शेवर पर जोर डाल देते हैं, जिससे त्वचा पर खरोंच लग सकती है या जलन हो सकती है।

हमेशा हल्के हाथों से शेवर चलाएं, ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे और आपको कोई परेशानी न हो।

इससे न केवल आपके बाल आसानी से हटेंगे, बल्कि आपकी त्वचा भी मुलायम और ताजगी भरी महसूस होगी।

शेविंग के बाद मॉइस्चराइजर न लगाना

शेविंग के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपकी त्वचा को नमी मिलती है और वह मुलायम रहती है।

अगर आप शेविंग के बाद मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो आपकी त्वचा रूखी हो सकती है और उसमें खुजली या जलन भी हो सकती है।

इसलिए, शेविंग के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और ताजगी भरी रहे। इन गलतियों से बचकर आप अपनी शेविंग प्रक्रिया को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं।

बच्चों को छोटी उम्र में ही तैराकी सिखाने के मिल सकते हैं ये 5 फायदे

बच्चों को छोटी उम्र में तैराकी सिखाना एक बेहतरीन विचार हो सकता है। इससे न केवल उनका शारीरिक विकास होता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना भी मिलती है। तैराकी सीखने से बच्चे पानी के प्रति डर को भी दूर कर सकते हैं और आपातकालीन स्थितियों में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इस लेख में हम 5 प्रमुख फायदों पर चर्चा करेंगे, जो बच्चों को तैराकी सिखाने से मिल सकते हैं।

शारीरिक विकास में मददगार

तैराकी एक ऐसी गतिविधि है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखती है। छोटे बच्चे जब तैराकी सीखते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनका शारीरिक विकास बेहतर होता है।

इसके अलावा तैराकी से बच्चों का संतुलन और तालमेल भी सुधरता है, जिससे वे शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं।

नियमित तैराकी से बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है और उनका शरीर लचीला भी बनता है।

बढ़ता है आत्मविश्वास

तैराकी सीखने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे पानी में तैरना सीखते हैं और इसमें माहिर होते हैं तो उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है।

वे खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पानी में समय बिताने से बच्चे अधिक आत्मनिर्भर बनते हैं और उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बेहतर होती है।

इससे उनका मानसिक विकास भी होता है।

आपातकालीन स्थितियों में खुद को रख सकते हैं सुरक्षित

तैराकी सीखने से बच्चे आपातकालीन स्थितियों में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कभी भी किसी तरह की दुर्घटना हो जाए या किसी को मदद की जरूरत पड़े तो बच्चे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

इसके अलावा तैराकी सिखाने से बच्चे पानी के प्रति जागरूक रहते हैं और उसमें सुरक्षित तरीके से समय बिताते हैं।

इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं।

सामाजिक संबंध बनाने का मिलता है मौका

तैराकी क्लासेस या स्विमिंग पूल पर जाकर बच्चे नए दोस्तों से मिलते हैं और सामाजिक संबंध बनाने का मौका मिलता है।

वे टीम वर्क सीखते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करना जानते हैं। इसके अलावा तैराकी सिखाने से बच्चों में सहयोग की भावना भी विकसित होती है।

इससे वे दूसरों की मदद करना और साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। तैराकी क्लासेस बच्चों के सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती हैं और उन्हें एकजुटता का अनुभव कराती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है लाभदायक

तैराकी केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। पानी में समय बिताने से मन शांत रहता है और तनाव कम होता है।

बच्चों को छोटी उम्र से ही तैराकी सिखाने से उनका मानसिक विकास भी बेहतर होता है। इससे वे अधिक संतुलित और खुश रहते हैं।

इस प्रकार बच्चों को छोटी उम्र में तैराकी सिखाना कई प्रकार से उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

आपने पूरा पढ़ लिया है

अमेरिका से टैरिफ जंग में भारत की लगी लॉटरी : भारतीय दवाओं के लिए यूरोप ने खोले दरवाजे, निर्यात को मिली हरी झंडी

अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच यूरोप ने भारतीय दवा उद्योग के लिए बड़ा अवसर पैदा किया है। सीडीएससीओ ने तीन भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ में एपीआई निर्यात की मंजूरी दी है। इससे भारतीय जेनेरिक दवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, निर्यात को गति मिलेगी और यूरोपीय बाजार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत होगी। हालांकि कंपनियों को सख्त गुणवत्ता मानकों का लगातार पालन करना होगा।

अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बीच यूरोप ने भारतीय दवा कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने कई भारतीय कंपनियों को यूरोपीय संघ (ईयू) में दवाओं के कच्चे पदार्थ यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) के निर्यात के लिए लिखित मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि ये कंपनियां अब यूरोप के सख्त गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कैंसर, एंटीबायोटिक और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एपीआई का निर्यात कर सकेंगी।

भारतीय कंपनियों को किन शर्तों पर मिली मंजूरी

सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया है कि मंजूरी मिलने के बाद भी सभी कंपनियों को लगातार गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। यदि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है, दवा की गुणवत्ता मानकों से कम पाई जाती है या स्थानीय अथवा अंतरराष्ट्रीय नियामकों की रिपोर्ट में कोई अनियमितता सामने आती है, तो इसकी जानकारी सात दिनों के भीतर देनी होगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में यह मंजूरी तत्काल निलंबित या रद्द की जा सकती है।

इस समझौते से भारत और यूरोप को क्या होगा फायदा

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर लगने वाले कर समाप्त होने से भारतीय जेनेरिक दवाएं यूरोप में और अधिक सस्ती तथा प्रतिस्पर्धी बनेंगी। साथ ही, प्रशासनिक लागत कम होगी और नियमों के सरल होने से दवाओं को यूरोप में मंजूरी मिलने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में तेज हो जाएगी।

किन भारतीय कंपनियों को मिली यूरोप में निर्यात की मंजूरी

यूरोपीय संघ में एपीआई निर्यात की मंजूरी पाने वाली कंपनियों में ऑनर लैब लिमिटेड (तेलंगाना), रवि बायोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र) और यूनीमैक्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

टाटा की छप्परफाड़ कमाई! सिर्फ 1 शेयर पर 1.10 लाख रुपए के डिविडेंड का ऐलान, मुनाफे ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

मुंबई, एजेंसी। अगर आपसे कहा जाए कि किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर रखने पर आपको एक लाख रुपये से ज्यादा की कमाई हो सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन देश के सबसे भरोसेमंद और दिग्गज औद्योगिक घराने टाटा समूह ने इसे सच कर दिखाया है। टाटा संस ने अपने शेयरधारकों पर धनवर्षा करते हुए प्रति शेयर 1 लाख 10 हजार रुपये से अधिक के ऐतिहासिक डिविडेंड (लाभांश) की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2025-26 के शानदार वित्तीय नतीजों का ऐलान करते हुए कंपनी ने बताया कि उसके नेट प्रॉफिट में भारी उछाल आया है, जिसने बाजार के सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है।

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन द्वारा जारी किए गए वित्त वर्ष 2026 के नतीजों के मुताबिक, कंपनी का राजस्व 9.1 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी के साथ 42,367 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 38,835 करोड़ रुपये रहा था। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी के शुद्ध मुनाफे (नेट प्रॉफिट) में 21.8 प्रतिशत का जोरदार उछाल दर्ज किया गया है, और यह बढ़कर 31,961 करोड़ रुपये हो गया है। इसी बंपर कमाई को देखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर 1,10,717 रुपये के बंपर डिविडेंड की सिफारिश की है। हालांकि, टाटा संस शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है और यह लाभांश शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए चेयरमैन चंद्रशेखरन ने बताया कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व निवेश के बावजूद टाटा समूह का कुल प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है। पूरे टाटा ग्रुप का कुल राजस्व 7.8 प्रतिशत बढ़कर 16,24,030 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया है, जबकि समूह का नेट प्रॉफिट 51.9 प्रतिशत की गजब की छलांग के साथ 1,70,525 करोड़ रुपये हो गया है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में अब टाटा समूह का कुल राजस्व 2.1 गुना और लाभ 5.4 गुना तक बढ़ चुका है, जो समूह की विभिन्न कंपनियों में किए गए बड़े सुधारों का ही नतीजा है।

एयर इंडिया बनी चिंता का सबब, घाटा बढ़कर 22 हजार करोड़ के पार

एक तरफ जहां पूरा टाटा समूह मुनाफे के नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया अभी भी कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में एयर इंडिया का घाटा बढ़कर 22,238 करोड़ रुपये हो गया है, जो इससे पिछले साल 10,859 करोड़ रुपये था। चेयरमैन ने इस भारी नुकसान की मुख्य वजहें बताते हुए कहा कि तेल की बढ़ती कीमतें, कई प्रमुख रूट्स का बंद होना, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रद्द171 विमान हादसे का एयरलाइन के कारोबार पर बेहद नकारात्मक असर पड़ा है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि इतिहास की किसी भी बड़ी एयरलाइन को दोबारा खड़ा होने में दशकों का समय लगता है और एयर इंडिया के कायाकल्प की दिशा में तेजी से और सकारात्मक काम किया जा रहा है।

जेब में जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट, 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों पर सरकार की हरी झंडी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में जल्द ही लेन-देन का अंदाज बदलने वाला है और लोगों के हाथों में कागज की बजाय प्लास्टिक (पॉलीमर) के चमचमाते नोट देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस अहम प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सबसे पहले 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। अगर यह परीक्षण हर पैमाने पर सफल रहता है, तो इन नोटों को देश भर में नियमित रूप से आम जनता के लिए चलन में जारी कर दिया जाएगा।

संसद में सरकार ने दी प्रस्ताव की जानकारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब के जरिए इस बड़ी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के तहत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था। इस योजना के शुरुआती चरण में 10 रुपये और 20 रुपये के 100-100 करोड़ पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए बाजार में उतारे जाएंगे। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद अब रिजर्व बैंक जल्द ही इस परीक्षण को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गया है।

क्या बंद हो जाएंगे पुराने कागजी नोट?

नए नोटों की खबर सामने आते ही आम लोगों के मन में पुराने नोटों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पारंपरिक कागजी नोटों को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। बाजार में पॉलीमर नोट और पहले से मौजूद कागज के नोट दोनों एक साथ चलन में बने रहेंगे। फील्ड ट्रायल के दौरान मुख्य रूप से यह परखा जाएगा कि भारत के अलग-अलग मौसम और परिस्थितियों में ये प्लास्टिक नोट कितने टिकाऊ साबित होते हैं और आम जनता को इनका इस्तेमाल करना कितना आसान लगता है।

क्यों पड़ी प्लास्टिक नोटों की जरूरत?

दुनिया के कई विकसित देशों में पॉलीमर नोट पहले से ही बेहद सफल रहे हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार, 10 और 20 रुपये जैसे छोटे मूल्य के नोटों का बाजार में सबसे ज्यादा लेन-देन होता है, जिसके चलते वे बहुत जल्दी फट या खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक के नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, जिससे बार-बार नए नोट छापने का सरकारी खर्च और कचरा दोनों कम होंगे। इसके साथ ही इन नोटों में पारदर्शी विंडो और आधुनिक सुरक्षा तकनीक जैसे कई नए फीचर्स जोड़े जा सकेंगे, जिससे जाली नोटों के कारोबार पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी।

अमेरिकी चुनाव में बढ़ेगा भारतवंशियों का दबदबा? डेमोक्रेटिक पार्टी ने दो उम्मीदवारों का किया समर्थन

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारतवंशी दो उम्मीदवार अमीश शाह और पिया दांडिया डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव अभियान में शामिल किए गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी नवंबर में होने वाले कांग्रेस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगलवार को शाह और दांडिया समेत पांच उम्मीदवारों को अपने 'रेड टू ब्लू' अभियान में शामिल किया। इस अभियान के तहत उन उम्मीदवारों को संगठन और धन जुटाने में मदद दी जाती है, जो रिपब्लिकन के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कड़ी चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं।

डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति 30 ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है, जिनके बारे में उसका मानना है कि वे नवंबर के चुनाव में रिपब्लिकन से अपनी सीटें छीन सकते हैं।

अमीश शाह पेशे से चिकित्सक हैं और पहले राज्य प्रतिनिधि रह चुके हैं। वह एरिजोना के पहले जिले से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार और राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के पूर्व खिलाड़ी जे फीली से है। जे फीली को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला हुआ है।

पिया दांडिया पहले हाईस्कूल की प्रधानाचार्य रह चुकी हैं। वह दक्षिण फ्लोरिडा के 22वें जिले से चुनाव लड़ रही हैं। यह क्षेत्र नए परिसीमन के बाद बनाया गया है और यहां कोई मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ रहा है।

भारत से अमेरिका आए माता-पिता की संतान पिया दांडिया ने पहले फ्लोरिडा के 21वें जिले से रिपब्लिकन नेता ब्रायन मास्ट को चुनौती देने की कोशिश की थी। ब्रायन मास्ट प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं।

डेमोक्रेटिक अभियान समिति के प्रमुख ने क्या कहा?

डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति की अध्यक्ष सुजान डेलबेने ने एक बयान में कहा, पिया एक कामकाजी मां हैं, जो नया भविष्य लिखना चाहती हैं। वह दक्षिण फ्लोरिडा के लोगों के लिए अमेरिकी सपने को ज्यादा आसान बनाना चाहती हैं। इसके लिए वह महंगाई की समस्या से निपटने, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर जैसी जरूरी योजनाओं की रक्षा करने और रिपब्लिकन नेताओं को उनके अधूरे वादों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमीश शाह का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा?

अमीश शाह एरिजोना विधानसभा के तीन बार सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति के समर्थन वाली उम्मीदवार और पूर्व पत्रकार मार्लेन गैलन-वुड्स को हराया था।गैलन-वुड्स इस साल डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति के समर्थन के बावजूद चुनाव हारने वाली तीसरी उम्मीदवार हैं। इससे पहले कैलिफोर्निया की जस्मीत बैन्स और मेन के जो बाल्डाची भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार होने के बावजूद हार चुके हैं। इंडियन-अमेरिकन इम्पैक्ट नाम के संगठन ने कहा, हम अपने लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय-अमेरिकी नेता प्रतिनिधि सभा पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह संगठन भारतीय मूल के अमेरिकियों को सरकार के हर स्तर पर समान प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए काम करता है। अमीश शाह का जन्म शिकागो में गुजराती माता-पिता के घर हुआ था, जो 1960 के दशक में भारत से अमेरिका जाकर बसे थे।

'चुनिंदा देशों का नहीं हो सकता एकाधिकार': यूएन सुरक्षा परिषद सुधार पर भारत का सख्त संदेश, किसे ठहराया जिम्मेदार?

यूएन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की धीमी रफ्तार पर भारत ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि 17 दौर की बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया कुछ देशों के संकीर्ण और विभाजनकारी हितों की बंधक नहीं बन सकती। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद में सुधार से जुड़ी अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) को अगले सत्र तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यह प्रक्रिया अब 18वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। सितंबर से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में इस पर फिर चर्चा होगी। भारत ने वार्ता आगे बढ़ाने के

फैसले का समर्थन किया, लेकिन सुधार प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी भी जताई। हरीश ने कहा कि 80वां सत्र भी पहले की तरह बिना किसी ठोस उपलब्धि के खत्म हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि आत्मा कई जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त करती है, लेकिन सुरक्षा परिषद सुधार के 17 चक्र पूरे होने के बाद भी कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा।

भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार तभी संभव है, जब स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सीटों का विस्तार किया जाए। केवल अस्थायी सीटें बढ़ाने से पांच स्थायी सदस्यों (P5) के निर्णय लेने के अधिकार में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत ने यह भी कहा कि अब लिखित मसौदे के आधार पर तय समयसीमा के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए। साथ ही वैश्विक दक्षिण को सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस महीने 2028-29 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत के अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। अगले साल जून में होने वाले चुनाव में एशिया-प्रशांत समूह की एक सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। भारत इससे पहले आठ बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। सबसे हाल में वह 2021-22 के कार्यकाल में परिषद का सदस्य था।

इटली, पाकिस्तान, तुर्किये और कनाडा के यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) समूह का प्रस्ताव है कि सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। यह समूह परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।

पश्चिम एशिया में जहाजों पर हमलों की निंदा

सुरक्षा परिषद की एक अलग बैठक में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा समेत कई व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई, एक लापता है और कई अन्य घायल हुए हैं। भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही हर हाल में बहाल होनी चाहिए।

भारत के लिए क्यों अहम है पश्चिम एशिया?

भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया उसकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और लाखों भारतीयों से सीधे जुड़ा हुआ क्षेत्र है।

खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं।

जीसीसी देशों के साथ भारत का सालाना व्यापार करीब 180 अरब डॉलर का है।

भारत को इन देशों से 52 अरब डॉलर से अधिक का प्रेषण (रेमिटेंस) और 31 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिलता है।

भारत ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताते हुए दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया। साथ ही यमन में हूतियों के हमलों और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमलों की भी कड़ी निंदा की। भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की।

'हम युद्ध रोकना चाहते हैं, पुतिन नहीं': जेलेंस्की बोले-रूस पर कड़े प्रतिबंध ही शांति का रास्ता, और क्या कहा?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सीनेट में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे शांति की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब भी युद्धविराम के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट के दोनों दलों के 60 से अधिक सांसदों से भी बातचीत की।

इसी दौरान अमेरिकी सीनेट ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक मतदान किया। इस

प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 12 वोट पड़े। जेलेंस्की ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह 'शांति की दिशा में पहला कदम'है। उन्होंने कहा कि यह वही प्रस्ताव है, जिस पर दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने लंबे समय तक काम किया था।

क्या पुतिन युद्ध रोकना नहीं चाहते?

फॉक्स न्यूज के होस्ट सीन हैनिटी को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन हर दिन युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन चाहता है। यूरोपीय देश भी चाहते हैं। लेकिन पुतिन नहीं चाहते।' जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन लगातार अस्थायी युद्धविराम की मांग कर रहा है ताकि राजनयिक बातचीत शुरू हो सके। लेकिन रूस इसके लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए रूस पर और दबाव बनाने और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।

लिंडसे ग्राहम का जिक्र क्यों किया?

जेलेंस्की ने दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को याद किया। उन्होंने कहा कि ग्राहम युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के मजबूत समर्थक थे। जेलेंस्की के मुताबिक, ग्राहम युद्ध के दौरान 10 बार यूक्रेन आए। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया, जिनमें मोर्चे के करीब के क्षेत्र भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ग्राहम को पूरा भरोसा था कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा और ऐसा ही हुआ।

यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर क्या चर्चा हुई?

जेलेंस्की ने अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह कंपनी ATACMS, HIMARS, F-16 और पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलें बनाती है। बैठक में संयुक्त उत्पादन, तकनीक के आदान-प्रदान और यूक्रेन की वायु रक्षा मजबूत करने पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों की टीमें संयुक्त उत्पादन शुरू करने के लिए ठोस समाधान पर काम कर रही हैं।'हम युद्ध रोकना चाहते हैं, पुतिन नहीं': जेलेंस्की बोले-रूस पर कड़े प्रतिबंध ही शांति का रास्ता; और क्या कहा?

क्या रूस को भारी नुकसान हो रहा है?

जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस हर महीने 30,000 सैनिक खो रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत में पुतिन ने दावा किया था कि रूस दो या तीन दिन में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने अपनी सैन्य तकनीक को तेजी से मजबूत किया है। अब देश में 500 कंपनियां रक्षा तकनीक के क्षेत्र में काम कर रही हैं और मोर्चे पर सैनिकों की मदद कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। युद्ध की पहल पहले जैसी रूस के हाथ में नहीं रह गई है।

पहले लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी, फिर शुरू होगा प्रोजेक्ट का काम... ग्रीन क्लीयरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। विकास और पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भविष्य में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी। काम शुरू होने के बाद मंजूरी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला केवल आगे से लागू होगा। पहले पर्यावरणीय मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने 2021 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को परियोजनाओं को काम होने के बाद या प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कुल 49 याचिकाओं पर अपना ये फैसला सुनाया है। ये याचिकाएं उन परियोजनाओं से जुड़ी थीं, जिन्होंने पर्यावरण के नियम तोड़े थे और उन्हें बाद में मंजूरी दी गई थी।

केंद्र सरकार के 2021 के आदेश के तहत कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के भी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकती थीं और बाद में सरकार से मंजूरी ले लेती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस 2021 वाले आदेश को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद माफी मांगने की यह व्यवस्था गलत है। आगे से कोई भी कंपनी बिना पहले इजाजत लिए अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी।

जिन कंपनियों या प्रोजेक्ट्स को इस पुराने नियम के तहत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, वे सुरक्षित हैं और उनका काम चलता रहेगा। अदालत ने कहा कि उनके ऊपर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छह दिनों की सुनवाई के बाद 1 अप्रैल 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार असाधारण स्थिति में और लोगों के बड़े हित में नोटिफिकेशन जारी करके सीमित समय के लिए एक बार की राहत योजना ला सकती है। मगर यह व्यवस्था कार्यालय ज्ञापन के जरिए नहीं बनाई जा सकती और न ही इसे उल्लंघनों को नियमित करने के स्थायी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल करके, अगर जरूरी समझे तो किसी परियोजना को काम के बाद पर्यावरण मंजूरी दे सकता है।

13 आरोपी-360 गवाह और 422 दस्तावेजनीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कोर्ट को क्या-क्या बताया?

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए गठित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। CBI ने कोर्ट को बताया कि 20 हजार पेज की चार्जशीट है। जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, साक्ष्य नष्ट करना, भ्रष्टाचार और लोक परीक्षा अधिनियम के तहत अपराध की धाराएं लगाई गई हैं।

सीबीआई के मुताबिक चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज, 43 भौतिक साक्ष्य हैं। 12 मई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने 8 साइबर विशेषज्ञ समेत 72 अधिकारियों की टीम बनाई थी और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त कर फोरेंसिक जांच की गई। सीबीआई ने बताया कि फोरेंसिक, हैंडराइटिंग और शैक्षणिक रिपोर्ट से लीक की पुष्टि हुई है।

कुल 13 लोगों को किया गिरफ्तार

सीबीआई के मुताबिक पहली गिरफ्तारी 13 मई 2026 को हुई थी। पेपर लीक मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें NTA के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इसके साथ ही बिचौलियों और कोचिंग से जुड़े 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। CBI ने बताया कि मनी ट्रेल की जांच चल रही है। कई बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट खाता फ्रीज किया गया है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया है। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट के एनेक्सचर दाखिल करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने नोट किया कि चार्जशीट में दस्तावेजों, बयानों और वस्तुओं की सूची संलग्न की गई है। कोर्ट ने CBI से पूछा कि चार्जशीट में जिन बयानों और अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वह कहां हैं। सीबीआई ने चार्जशीट के एनेक्स्चर दस्तावेज़ को दाखिल करने के लिए समय मांगा। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 20,000 पृष्ठों के एनेक्स्चर दस्तावेज़ को स्कैन किया जा रहा है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

अब फुटबॉल मैदान में जलवा बिखेरेंगे टाइगर श्रॉफ, प्रोफेशनल डेब्यू की तैयारी में एक्टर ; डूरंड कप में आएंगे नजर!

एक्टर टाइगर श्रॉफ मुंबई एफसी की टीम में शामिल किया गया है और वह जल्द ही डूरंड कप में अपना प्रोफेशनल फुटबॉल डेब्यू कर सकते हैं।

मुंबई एफसी के को-ओनर जोहेब अमरानी के मुताबिक, टाइगर इस समय टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और शिलॉन्ग में होने वाले ग्रुप स्टेज मैच के लिए टीम के साथ सफर भी कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'टाइगर टीम में रजिस्टर हो चुके हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। टाइगर जैसे बड़े स्टार के साथ सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखना होगा, खासकर छोटे शहरों में जहां भीड़ ज्यादा हो सकती है।'

उन्होंने आगे कहा, 'सोशल मीडिया आजकल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमने उनसे एक तारीख भी तय की है। अगर सब ठीक रहा, तो वह एक मैच के लिए जरूर टीम के साथ जाएंगे। फिलहाल वह टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।'

जोहेब अमरानी ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2023 में एक इंफ्लुएंसर्स लीग के दौरान टाइगर का खेल देखा था, जहां रणबीर कपूर और महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल थे।

मुंबई एफसी का डूरंड कप शेड्यूल

मुंबई एफसी अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच शिलॉन्ग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलेगी। टीम 3 अगस्त को लांग्सनिंग एससी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 8 अगस्त को शिलॉन्ग लाजोंग और 11 अगस्त को नोंगकसेह एसएस एंड सीसी के खिलाफ मुकाबले होंगे। अब फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि क्या टाइगर श्रॉफ मैदान में उतरकर अपने फुटबॉल स्किल्स से भी सबका दिल जीत पाएंगे या नहीं।

अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने बिखेरा जलवा, हाथों में हाथ डालकर किया रैंप वॉक, वीडियो हुआ जमकर वायरल

इंडियन सिनेमा की पसंदीदा जोड़ी अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने ICW 2026 में अपने रॉयल अंदाज से सबका दिल जीत लिया। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास।

मंगलवार शाम नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया कुट्योर वीक में दोनों डिजाइनर जयंती रेड्डी के शोस्टॉपर बने। अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ ने हाथों में हाथ डालकर रैंप वॉक किया और अपनी केमिस्ट्री से शो को खास बना दिया। उनका लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, जो जयंती रेड्डी के कलेक्शन को पूरी तरह कॉम्प्लिमेंट कर रहा था।

अदिति ने गोल्ड और बेज रंग का खूबसूरत आउटफिट पहना, जिसमें पेप्लम स्टाइल ब्लाउज और शरारा स्कर्ट थी। इस पर बारीक जरदोजी, बीडवर्क और सीक्विन का काम किया गया था। उन्होंने चोकर सेट, स्ट्रेट हेयर और बोल्ड लिप्स के साथ अपना लुक पूरा किया। वहीं सिद्धार्थ ने बेज रंग की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी जैकेट पहनी, जिसे उन्होंने धोती स्टाइल ट्राउजर के साथ कैरी किया। उनके लुक को पर्ल और एमराल्ड की मल्टी-लेयर नेकलेस ने और खास बना दिया।

जयंती रेड्डी का कलेक्शन 'द गिल्डेड एरा' हैदराबाद की संस्कृति और निजामी दौर की कला से प्रेरित था। इसमें ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, फ्लोरल डिजाइन और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया, जो भारतीय कारीगरी की खूबसूरती दिखाते हैं। शो के आखिर में अदिति, सिद्धार्थ और जयंती रेड्डी ने साथ में पोज दिया, जो इस इवेंट का सबसे यादगार पल बन गया।

'मुझे लगा मेरा बेटा आ गया' ; शबाना आजमी ने साझा किया 'बंटवारा' का किस्सा ; बोलीं- 'सनी देओल मेरे रक्षक बने'

फिल्म 'बंटवारा 1947' अगले महीने अगस्त में सिनेमाघरों में लगेगी। नाम से ही स्पष्ट है कि यह भारत-पाकिस्तान विभाजन पर बनी फिल्म है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आज मंगलवार को आयोजित ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी, एक्टर सनी देओल के अलावा अन्य कास्ट भी मौजूद रही। जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी पहुंचे। शबाना आजमी ने फिल्म के एक मुश्किल सीन का जिक्र किया।

शबाना आजमी ने फिल्म के एक सीन के बारे में चर्चा करते हुए सनी देओल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सीन काफी मुश्किल था। जब सनी देओल आए तो उन्हें लगा कि उनका बेटा आ गया। अभिनेत्री की बात सुन सनी देओल भावुक हो गए। बता दें कि शबाना आजमी इस फिल्म में माई के रोल में हैं। फिल्म के एक सीन को अभिनेत्री ने 50 साल के करियर में सबसे मुश्किल सीन बताया। उन्होंने कहा, 'फिल्म में एक ऐसा सीन है जो बहुत ह्यूमिलिएटेड है। उस सीन में विलेन मुझे खींचकर लेकर जाता है। मेरा कुर्ता फाड़ देता है। फिर, सनी देओल आकर मेरे ऊपर दुपट्टा डालते हैं। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बेटा आ गया। वे मेरे प्रोटेक्टर बने। मैंने उन्हें गले लगाया और ईश्वर का शुक्रिया कहा कि ये मेरे पास हैं। इन्होंने मुझे बचाया। मैं बहुत बेबस थी'।

सनी देओल ने कहा- 'मां पर थोड़ी भी आंच आई तो दुनिया भाड़ में जाए'

शबाना आजमी ने आगे कहा, 'एक कलाकार के तौर पर 50 साल के अनुभव के साथ इस सीन को मैंने बहुत सच्चाई के साथ महसूस किया। ऐसा मेरे को-एक्टर की वजह से हुआ कि यह सीन फिल्म में बहुत शानदार लगेगा। मैं सनी देओल को थैंक्यू कहना चाहती हूं'। इस दौरान सनी देओल भी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, 'मैं जो भी फिल्म करता हूं, मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूं। मैं उसी तरह से हर चीज में यकीन करता हूं। शबाना जी मेरी मां की भूमिका में हैं। मेरा जो किरदार है, कहता है। मां के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आ जाए तो दुनिया भाड़ में जाए'। बता दें शबाना आजमी ने जिस सीन का जिक्र किया, उसकी झलक ट्रेलर में भी है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

इसके अलावा शबाना आजमी ने देओल परिवार के साथ काम करने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, 'मेरी इससे पहले जो फिल्म पर्दे पर आई थी वो धरम जी के साथ थी, 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अब यह फिल्म सनी देओल ओर करण के साथ है। मैंने अभय देओल के साथ भी काम किया है। अब बॉबी से कहिए कि वे भी तैयार हो जाएं'। इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट प्रीति जिंटा हैं। आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com